सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 320, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

नाग साँप सहमे सभी,
देख आदमी खोट।
जहर उगलते हैं सदा,
मुस्कानों की ओट।

जंगल बामी सब मिटे,
और रसायन खेत।
साँप नाग सब मर रहे,
रे मानुष तू चेत।

आस्तीनों के नाग हैं,
हरपल रहते संग।
पता नहीं कब काटलें,
सदा बदलते रंग।

सावन पावन चल रहा,
नागपंचमी आज।
सबका मंगल हो सदा,
पूरण हों सब काज।

- डॉ. सुशील शर्मा

प्रसंगवश

संगीत कार्यक्रम को लेकर एसजीपीसी व पंजाब सरकार में टकराव क्यों?

चितलीन सेठी

गुरु तेग बहादुरजी की शहादत के 350 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में श्रीनगर में पंजाब सरकार के भाषा विभाग द्वारा आयोजित एक 'गंभीर और आध्यात्मिक' संगीत कार्यक्रम के दौरान दर्शकों के लोकगीतों पर नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पंजाब में विवाद खड़ा हो गया है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने इसे 'गंभीर रूप से पीड़ादायक' बताया, जबकि सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और भाषा विभाग के निदेशक जसवंत सिंह जफर को इस मामले में शनिवार को तलब किया।

यह दो दिवसीय कार्यक्रम बुधवार से शुरू हुआ था, जिसे जम्मू-कश्मीर सरकार की कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस आयोजन में लोक गायक बीर सिंह को धार्मिक और सूफी गीतों की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था। बैंस और जफर को 1 अगस्त को पांच सिंह साहिबान (उच्चतम धार्मिक पदाधिकारियों) की सभा के समक्ष उपस्थित होकर सफाई देने के लिए कहा गया है।

बैंस ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि वह एक विनम्र सिख की तरह अकाल तख्त के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने कार्यक्रम में जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी स्वीकार की और क्षमा मांगी।

लोक गायक बीर सिंह ने भी शुक्रवार को बिना शर्त माफी मांगी, यह कहते हुए कि कार्यक्रम को लेकर जो हुआ वह 'अनजाने में हुई चूक' थी। उन्होंने अकाल तख्त को एक माफीनामा भेजा है। बाद में उसी दिन वह स्वर्ण मंदिर परिसर स्थित अकाल तख्त पर व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और क्षमा मांगी।

जसवंत सिंह ज़फर ने व्हाट्सएप के ज़रिए 14 जुलाई की वह आमंत्रण-पत्र साझा किया जो पंजाब भाषा विभाग ने बीर सिंह को भेजा था। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्हें गुरु तेग बहादुर जी की बाणी और सूफी गीत गाने हैं। जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी की सचिव हरविंदर कौर ने कहा कि अकादमी की इस कार्यक्रम में भूमिका सीमित थी। हम इसकी जांच कर रहे हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि श्रीनगर में एक मजबूत सिख समुदाय है और कई लोग इस दो दिवसीय कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और एसजीपीसी के बीच इस बात को लेकर तनाव है कि नवंबर में गुरु तेग बहादुरजी की शहादत के 350 साल पूरे होने का मुख्य कार्यक्रम कौन आयोजित करेगा।

इस हफ्ते की शुरुआत में मुख्यमंत्री मान ने घोषणा की थी कि इस अवसर पर पंजाब सरकार भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करेगी। इस पर एसजीपीसी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने का 'अधिकार केवल' एसजीपीसी को है और राज्य सरकार द्वारा समानांतर कार्यक्रम करना धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के बराबर है। जवाब में मुख्यमंत्री मान ने टिप्पणी की थी कि एसजीपीसी के पास धार्मिक आयोजनों का कोई 'कॉपीराइट' नहीं है।

गुरु तेग बहादुर, सिखों के नौवें गुरु, को मुगल शासक औरंगज़ेब के आदेश पर 24 नवंबर 1675 को दिल्ली में शहीद किया गया था। उनकी शहादत की स्मृति में गुरुद्वारा सीस गंज साहिब (जहां उन्हें शहीद किया गया) और रकाब गंज साहिब (जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ) का निर्माण हुआ।

गुरु तेग बहादुर की शहादत को सिख इतिहास की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक माना जाता है। यह वही घटना है जिसने आगे चलकर 1699 में उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

हालांकि, कार्यक्रम वैसा नहीं रहा जैसा सोचा गया था। शुक्रवार शाम बीर सिंह के कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वे लोकगीत गा रहे थे और दर्शक कुर्सियों से उठकर नाच रहे थे। माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने कहा कि इस कार्यक्रम में सिख आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और पंजाब सरकार से माफी की मांग की। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने प्रेस बयान में कहा, 'सरकारी कार्यक्रम में जो प्रस्तुत किया गया वह शहादत और सिख मर्यादा–गुरमत मर्यादा–दोनों के लिए अपमानजनक था। पंजाब के भाषा विभाग ने इस गंभीर अवसर को एक मनोरंजन कार्यक्रम में बदलकर सिखों की भावनाओं को गहराई से ठेस पहुंचाई है।'

सोशल मीडिया पर आलोचना बढ़ने के बाद गायक बीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, 'मैं सीधे ऑस्ट्रेलिया से श्रीनगर आया था और मेरा मोबाइल बंद हो गया था। मेरे मैनेजमेंट ने मुझे कार्यक्रम की प्रकृति के बारे में सही जानकारी नहीं दी। जब हमें गलती का अहसास हुआ तो कार्यक्रम का समापन विशेष अरदास से किया, जिसमें दर्शकों से जूते उतारने और सिर ढकने की अपील की गई।'

शनिवार को जब बैंस और जाफर को अकाल तख्त द्वारा तलब किया गया, तब जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने प्रेस बयान में कहा कि 'गुरु साहिब की शहादत शताब्दी के इतिहास में पहली बार कोई कार्यक्रम गीत-संगीत और नाच-गाने से शुरू हुआ, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। 1 अगस्त की बैठक में पंथक और धार्मिक मसलों पर चर्चा होगी और बैंस व जाफर दोनों से उनका पक्ष सुना जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बीर सिंह अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए थे और माफी मांग चुके हैं, जिसे भी उच्च पंथिक सभा में विचार में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आनंदपुर साहिब को सफेद रंग में सजाना चाहती है, टेंट लगाना चाहती है या श्रद्धालुओं के लिए अन्य व्यवस्थाएं करना चाहती है, तो एसजीपीसी उसका स्वागत करेगी। उन्होंने कहा, 'लेकिन किसी केंद्रीय सिख धार्मिक संस्था के समानांतर कार्यक्रम आयोजित करना स्वीकार नहीं है।'

उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसजीपीसी पर तंज कसते हुए कहा कि 'सिख धर्म पर एसजीपीसी का कॉपीराइट नहीं है। जब शिरोमणि अकाली दल की सरकार धार्मिक शताब्दी कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, तब एसजीपीसी ने कभी नहीं कहा कि वे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।' इसके जवाब में एसजीपीसी ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सिख संस्थाओं को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। ऐतिहासिक रूप से, सिख विरासत और इतिहास से जुड़े शताब्दी समारोह खालसा पंथ की अगुवाई में होते रहे हैं, जिनमें सभी सिख संप्रदाय और संस्थाएं शामिल होती हैं, जबकि सरकारें सहयोग करती रही हैं।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस

हमारी मूल प्रवृति बुद्ध की है युद्ध की नहीं, परीक्षा में पेन-पेंसिल टूटने की चिंता नहीं हो : राजनाथ सिंह

● गोगोई ने पूछा- पीओके कब्जा क्यों नहीं किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में सोमवार दोपहर 2:05 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, 'हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं-बहनों के सिंदूर का बदला लिया।' रक्षा मंत्री ने 55 मिनट के भाषण में कहा- हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया। हमने किसी के दबाव में पाकिस्तान से सीजफायर नहीं किया।

राजनाथ सिंह ने कहा- विपक्ष पूछ रहा है कि युद्ध में हमारे कितने फाइटर जेट गिरे? उन्होंने यह नहीं पूछा कि हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मनों के कितने जेट गिराए? परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है। कितनी पेंसिल टूटी या पेन गुमे, यह पूछना बेईमानी है।

● देश जानना चाहता है कि 5 दहशतगर्द पहलगाम में कैसे घुसे?

विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा- हम सरकार से सवाल पूछेंगे। देश जानना चाहता है कि 5 दहशतगर्द पहलगाम में कैसे घुसे? उनका क्या मकसद था? सरकार कहती है हमारा मकसद युद्ध नहीं था। हम जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहते थे। हम पूछेंगे, क्यों नहीं था। होना चाहिए था। पीओके आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे।

एसआईआर मुद्दे पर हंगामा - संसद में 11 बजे से कार्यवाही शुरू हुई थी। पहले विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) मुद्दे पर हंगामा किया।

आपने रोका क्यों?... जब अचानक राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को भाषण के बीच में टोका

सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर बोल रहे थे तभी राहुल गांधी ने अचानक सवाल पूछा कि 'आपने क्यों रोका?'। यह सवाल उन्होंने तब किया जब राजनाथ सिंह ने बताया कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत युद्ध रोकने के लिए राजी हो गया था। इस बहस में पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते और सीमा पर हुए आतंकी हमलों पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी के इस सवाल ने बहस को और भी गंभीर बना दिया। राजनाथ सिंह जब यह कह रहे थे कि उन्होंने (पाकिस्तान) हमारे डीजीएमओ को फोन किया और कहा, महाराज, अब रोक दीजिए सर; बहुत हो गया, और हमने उनकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त के साथ..., तभी राहुल गांधी ने उन्हें टोक दिया। राहुल गांधी तुरंत खड़े हुए और पूछा, तो आपने (कार्रवाई) रोकी क्यों? राहुल गांधी के सवाल से सत्ताधारी पार्टी के सांसद नाराज हो गए। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, मैंने इस बारे में अपने भाषण में विस्तार से बताया है।

जयशंकर बोले- मोदी-ट्रम्प में कोई बात नहीं हुई, शाह बोले- कांग्रेस को किसी और देश पर भरोसा

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रम्प के सीजफायर दावे पर कहा– 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत नहीं हुई। किसी भी स्टेज पर अमेरिका से चर्चा के दौरान व्यापार पर बात नहीं हुई। इस बात पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।

अमित शाह– यह देखते हुए अमित शाह बीच में उठे और कहा– भारत का विदेश मंत्री यहां बयान दे रहा है, पर विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है। किसी और देश पर भरोसा है। विदेश मंत्री पर भरोसा क्यों नहीं करते। इसलिए विपक्ष में बैठे हैं।

सेना का श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव

● पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकी ढेर

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने आज संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद श्रीनगर के हरवान इलाके के लिडवास क्षेत्र में 'ऑपरेशन महादेव' चलाया। इसके तहत सेना ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक, ये आतंकी प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) संगठन से जुड़े हुए थे, साथ ही ऐसी भी सूचना मिल रही है कि पहलगाम हमले में शामिल जिन तीन आतंकियों का स्कैच जारी किया गया था, शायद ये वही हैं। भारतीय सेना की चिनार कोर द्वारा एक्स हैंडल पर भी पोस्ट डाला गया था कि लिडवास इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है और तीन आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। इस पूरे अभियान की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही थी। सूचना है कि जैसे ही सेना के जवान संदिग्ध स्थान के पास पहुंचे, तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कार्रवाई में तीन आतंकी ढेर हुए हैं।

आतंकी हाशिम मूसा ढेर - सूत्रों के मुताबिक, इस ऑपरेशन में पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमांइड हाशिम मूसा के भी ढेर होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा स्कैच में दिख रहे दो और आतंकी सुलेमान और यासिर के भी मारे जाने की जानकारी मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में किया प्रदर्शनी 'सदानीरा' का शुभारंभ

प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर केंद्रित है प्रदर्शनी

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार ने 30 मार्च से 30 जून 2025 तक 90 दिवसीय जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया। सम्पूर्ण प्रदेश में चले इस अभियान में जनभागीदारी की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। स्थानीय नागरिकों ने जल संरक्षण के प्रति अपनी सहभागिता सुनिश्चित की नदियों, जलस्रोतों व जल संरचनाओं को संरक्षित करने 2 लाख 30 हजार 740 से अधिक जलदूतों ने पंजीयन कराया। अभियान के अंतर्गत अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए मध्यप्रदेश में 84 हजार 726 खेत तालाब, 1 लाख 4 हजार 276 कूप रिचार्ज पिट और 1283 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया। इतना ही नहीं जल संचय करने वाले जिलों में खंडवा देशभर में नबर वन बना और राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश, देश में चौथे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर केंद्रित प्रदर्शनी 'सदानीरा' का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों, प्रदेश की बावड़ियों, जलीय जीवन के प्राणतत्व-जलचर, अमृतस्य नर्मदा, उपग्रह की नजर से प्रदेश की प्रमुख जल संरचनाओं जैसी प्रदेश की जलीय विविधता को वीर भारत न्यास द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

नदी संरक्षण वैज्ञानिक दायित्व के साथ सांस्कृतिक चेतना का भी है आह्वान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस अभियान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की एक अलग पहचान स्थापित की है। यह अभियान अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। अभियान की अभूतपूर्व उपलब्धियों को प्रदर्शनी के रूप में संयोजित किया गया है। यह प्रदर्शनी नदियों और जल स्त्रोतों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने का एक सांस्कृतिक प्रयास है।

चिदंबरम बोले-कैसे पता चला कि पहलगाम आतंकी पाकिस्तान से आए

● एनआईए के पास इसका क्या सबूत, हमलावर देश के भी तो हो सकते हैं

नईदिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का पहलगाम हमले पर 2 दिन पहले दिए बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने कहा था कि कैसे पता कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री का यह बयान संसद में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के कुछ घंटे पहले आया। चिदंबरम ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा, 'वे (एनआईए) यह बताने को तैयार नहीं हैं कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया?

पटना में कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र जारी

● पिता का नाम कुत्ता बाबू, मां का नाम कुतिया देवी लिखा, डीएम ने दिए जांच के आदेश

पटना (एजेंसी)। पटना के मसौढ़ी में एक कुत्ते के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद पटना के वरिष्ठ अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सर्टिफिकेट में नाम डॉग बाबू लिखा है। पिता का नाम कुत्ता बाबू और मां का नाम कुतिया देवी लिखा है।

पटना के डीएम त्याग राजन ने सोमवार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मसौढ़ी अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा है।

24 घंटे के अंदर डीएम ने मांगी है रिपोर्ट

जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मसौढ़ी अनुमंडलाधिकारी ने बताया कि किसी ने फर्जी तरीके से आवेदन कराया है। उन्होंने कहा कि वे इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं। इस एप्लिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। प्रमाण पत्र की स्थिति देखने पर यह रिजेक्ट दिखा रहा है, जबकि इसे आवेदन करते वक्त ही रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए था। जिलाधिकारी ने सोमवार को एक्स पर बताया कि मसौढ़ी अंचल में 'डॉग बाबू' के नाम से रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी हुआ है। मामला संज्ञान में आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है।

लुधियाना में नहर में गिरी पिकअप, 7 श्रद्धालुओं की मौत

इनमें 2 बच्चे भी, 3 लापता

लुधियाना (एजेंसी)। पंजाब के लुधियाना में रविवार देर रात मलेरकोटला रोड पर जगेड़ा नहर के पुल से महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें से 2 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 3 लोग नहर में लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35°c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 29 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

ओपन एआई सीईओ की चेतावनी!

'18 साल बाद बदल जाएगी दुनिया, लगता नहीं मेरा बेटा कॉलेज जाएगा'

नईदिल्ली (एजेंसी)। आजकल हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये एक ऐसी तकनीक है, जिससे मशीनें इंसानों की तरह सोच और काम कर सकती हैं। एआई ने तेजी से हर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है, जो शिक्षा समेत कई उद्योगों में बदलाव ला रहा है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एआई के दौर में एजुकेशन के फ्यूचर को लेकर बात की।

क्या वाकई शिक्षा का पुराना तरीका है खतरे में?- शिक्षा के भविष्य को लेकर उनकी राय है कि जिस तरह से एआई तेजी से अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में शिक्षा का पुराना तरीका शायद ही बचे। इतना ही नहीं उन्हें तो यह भी नहीं लगता कि उनका बेटा आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाएगा।

हालांकि, उन्होंने एजुकेशन पर एआई के सकारात्मक पहलुओं के बारे में भी बात की। सैम ने कहा एआई सीखाने के तरीकों में बड़े बदलाव लाएगा, लेकिन इससे इंसानों की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। चलिए जानते हैं कि आखिर ऑल्टमैन को ऐसा क्यों लगता है कि पारंपरिक शिक्षा का भविष्य खतरे में है।

बदल जाएगा शिक्षा का तरीका- कॉमेडियन थियो वॉन के साथ 'दिस पास्ट वीकेंड' पॉडकास्ट पर बात करते हुए ऑल्टमैन ने एआई के एजुकेशन और जॉब पर होने वाले असर के बारे में भी बात की। ऑल्टमैन को लगता है कि पिछले कुछ महीने बहुत तेजी से बीते हैं।

एआई हमेशा छात्रों से ज्यादा होगा स्मार्ट

ऑल्टमैन का कहना है कि जिस तरह से एआई के काम करने का तरीका है, उस हिसाब से यह हमेशा ही स्टूडेंट्स के ज्यादा स्मार्ट होगा। हालांकि, ऑल्टमैन का कहना है कि एआई स्टूडेंट्स की लर्निंग मैथड को भी बदलेगा। उनके मुताबिक एआई सीखने का एक नया तरीका है। उन्होंने कैलकुलेटर का उदाहरण देते हुए कहा कि एआई भी कैलकुलेटर की तरह शिक्षा को और बेहतर बनाएगा। इस दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनका बेटा कॉलेज पढ़ने जाएगा। खुद सैम ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 2005 में पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि वह दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे। उनका मानना है कि एआई के आने से पारंपरिक कॉलेजों की जरूरत कम हो जाएगी।

- **युवाओं से ज्यादा बुजुर्गों की चिंता-** हालांकि, इन सबके बीच उनके लिए भी यह चिंता का विषय है कि युवा पीढ़ी के लिए तो एआई के साथ तालमेल बिठाना आसान होगा, लेकिन पुरानी पीढ़ी एआई को कैसे अपनाएगी? ये पहले भी हुआ है कि युवा नई टेक्नोलॉजी को आसानी से अपना लेते हैं, जबकि बुजुर्गों को मुश्किल होती है। ऐसे में उन्हें पारंपरिक शिक्षा और काम करने के पुराने तरीके को छोड़ने में बहुत दिक्कत होगी।
- **लगातार अपनाने की प्रक्रिया है तकनीक-** वह कहते हैं कि हो सकता है आने वाली पीढ़ी को हमारी दुनिया बहुत सीधी-सादी लगेगी। यही होता आया है। पुरानी पीढ़ी के लोग भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। 100 सालों बाद शायद हमें भी भविष्य ऐसा ही दिखाई दे। इसका मतलब यह है कि तकनीक तो आती जारी रहेगी ही, इसे अपनाना एक सतत प्रक्रिया है, जो हमेशा चलती रहेगी। एआई एक ऐसा टूल है, जो हमारे काम करने और सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।
- **एआई के साथ खुद को करना होगा तैयार-** सैम ऑल्टमैन की इन बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का हमारी लाइफ पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर पर फिलहाल रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

- कहा- आधार और वोटर आईडी पर विचार करे चुनाव आयोग

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग को अहम सुझाव दिया है। कोर्ट ने एक बार फिर आयोग से कहा है कि वह इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को पहचान के वैध दस्तावेज के रूप में शामिल करने पर विचार करे। बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयोग से कहा है कि वह बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के दौरान आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को पहचान के वैध दस्तावेज के रूप में मानने पर विचार करे।

चंद्रमौलेश्वर के साथ शिव-तांडव स्वरूप में दर्शन देने निकले महाकाल

उज्जैन (एजेंसी)। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दोपहर एक बजे तक 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। विनायक चतुर्थी होने के कारण भगवान महाकाल का गणेश स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। उज्जैन के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में भक्त बाबा भोलेनाथ का पूजन-अभिषेक करने पहुंचे। उज्जैन में शाम को महाकाल की तीसरी सवारी मंदिर से निकली।

27 फीसदी आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतरी ओबीसी समाज

सीएम हाउस के घेराव को निकले ओबीसी कार्यकर्ताओं को रंगमहल टॉकीज पर पुलिस ने रोका

भोपाल(नप्र)। 27 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा का उग्र प्रदर्शन सोमवार को राजधानी में हुआ। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रंगमहल टॉकीज के पास ही रोक दिया। इस दौरान तेज बारिश होती रही, लेकिन ओबीसी कार्यकर्ता सड़कों पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे।

प्रदर्शनकारी जवाहर चौक से नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़े, लेकिन रंगमहल टॉकीज के पास भारी पुलिस बल ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। यहां महासभा के पदाधिकारियों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

कई बार पुलिस से हुई धक्का-मुक्की- बारिश में भीगते हुए भी ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार हल्की धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी।

उमंग सिंगार ने किया समर्थन- प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता उमंग सिंगार भी पहुंचे और ओबीसी महासभा की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार पिछड़े वर्ग के हक को लगातार नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस इस लड़ाई में ओबीसी वर्ग के साथ खड़ी है।

महासभा ने तीन प्रमुख मांगें रखीं- शासकीय नौकरी में होल्ड किए गए 13 प्रतिशत आरक्षण को तत्काल अनहोल्ड कर 27 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार नियुक्तियां की जाएं।

शासकीय सेवा में पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए।

जातिगत जनगणना कराई जाए, जनसंख्या आंकड़े सार्वजनिक हों और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू किया जाए।

आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी, उस अनुपात में भागीदारी नहीं

महासभा का आरोप है कि प्रदेश की आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की होने के बावजूद सरकारी नौकरी, प्रशासन, पुलिस, शासन और निजी क्षेत्र तक में उनकी भागीदारी नहीं है। महासभा के नेताओं ने कहा कि 90 के दशक में 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक मध्यप्रदेश में यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सका।

13 फीसदी आरक्षण होल्ड करना अन्याय

एड. धर्मेंद्र कुशवाह ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने 13 फीसदी ओबीसी आरक्षण होल्ड कर रखा है, जिससे कई अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं। यह न सिर्फ संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक न्याय का खुला उल्लंघन भी है। सरकार रोजगार के वादे कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब बेरोजगारी को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर महासभा ने प्रदर्शन कर सरकार को चेताया था कि यदि होल्ड वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा।

संविधान विरोधी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई

प्रवक्ता एड. विश्वजीत रतौनिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, इसके बावजूद सरकार ने अब तक ठोस कदम नहीं उठाया। यह सरकार की संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हम इस मानसिकता के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी ने सवाल उठाया कि सरकार ने 7 फीसदी अपर कास्ट को 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो दे दिया, लेकिन 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लागू करने से पीछे क्यों हट रही है। सरकार को तत्काल प्रभाव से यह आरक्षण देना चाहिए।

कांवड़ जल एवं दूध से पशुपतिनाथ का अभिषेक

भोपाल। श्री पशुपतिनाथ नेपाली समाज मंदिर गोविन्दपुरा में सोमवार को 300 से अधिक कावड़ियों व श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के जल एवं दूध से भगवान श्री पशुपतिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के दौरान कार्यपालक निदेशक, भेल पी.के. उपाध्याय, पार्षद अशोक वाणी, महेश मालवीय सहित समाज के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। समाज के अध्यक्ष

लोकमणी घिमिरे एवं महामंत्री सुरेश पाण्डे ने बताया कि 26 जुलाई को नेपाली समाज के 300 से अधिक कावंड़ यात्री बुधनी घाट, नर्मदापुरम से कांवड़ लेकर बोल बम और श्री पशुपतिनाथ भगवान के जयकारों के साथ रवाना होकर रास्ते में रात्रि विश्राम के बाद 27 जुलाई को दोपहर भोपाल के गणेश मंदिर, हबीबगंज पहुचंने पर समाज के पदाधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अगुवानी कर स्वागत किया गया। डॉ. जीवलाल सापकोटा 'जीवन' ने बताया कि यह कावड़ यात्रा विभिन्न रास्तों से होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची। सोमवार को प्रातः 8 बजे कावड़ यात्रियों द्वारा लाये गये नर्मदा जल तथा दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया।

जैसलमेर में स्कूल का गेट गिरने से छात्र की मौत

टीचर-5 साल की बच्ची घायल

जैसलमेर (एजेंसी)। जैसलमेर के पूनमनगर में सरकारी स्कूल का गेट गिरने से 1 छात्र की मौत हो गई। जबकि एक टीचर और 5 साल की बच्ची के भी चोटें आई है। टीचर को जवाहिर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का मैन एंट्री गेट गिरने से यह हादसा हुआ।

जालंधर-अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई रुकी, 3 की मौत

डायरेक्टर बोले- छुट्टी पर था ऑपरेटर

जालंधर (एजेंसी)। जालंधर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उस समय हड़कंप मच गया, जब आईसीयू में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई 2 मिनट के लिए बाधित हो गई। इस दौरान तीन मरीजों की मौत हो गई और दो की हालत बिगड़ गई, जिन्हें बाद में उपचार के बाद बचा लिया गया।

घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जैसे ही मामला सरकार तक पहुंचा तो, रात को करीब सवा एक बजे स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों से मीटिंग की।

सोमवार सुबह भी हालात पर नजर रखने के लिए मंत्री दोबारा अस्पताल पहुंचे। वहीं, दोपहर में पंजाब सरकार के मंत्री मोहिंदर भगत भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।इसके साथ ही चंडीगढ़ से पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉ. अनिल अग्रवाल ने अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया।

कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ युद्धविराम की घोषणा की

बैंकॉक/नोम पेन्ह (एजेंसी)। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने थाईलैंड के साथ चल रहे सीमा विवाद में युद्धविराम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए तत्काल लड़ाई रोकने की उम्मीद है।

मलेशिया ने इस सीजफायर में मध्यस्थता की है। दोनों देशों के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर आज शांति वार्ता हुई। इस बैठक में थाईलैंड की तरफ से कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई और कंबोडिया की तरफ से प्रधानमंत्री हुन मानेट ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की।

डिप्टी कमिश्नर के भोपाल वाले फ्लैट पर ईओडब्ल्यू का छापा

आरामगाह में मिला लाखों रुपए का घरेलू सामान-महंगी शराब-बैंक पासबुक, पूछताछ के बाद से जगदीश सरवटे लापता

जबलपुर (नप्र)। लंबे समय तक जबलपुर में तैनात आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे की आय से अधिक संपत्ति की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। जबलपुर (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) की टीम को सरवटे का भोपाल में एक फ्लैट होने की जानकारी मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने सोमवार को दिन भर फ्लैट की तालाशी ली।

सर्चिंग के दौरान भोपाल के थाना मिसरौद अंतर्गत फ्लैट से लाखों रुपए का घरेलू सामान के साथ-साथ महंगी शराब और बैंक पासबुक मिली है। जगदीश सरवटे ने 2021 में इस फ्लैट को अपने आरामगाह के लिए खरीदा था, जहां पर रोजमर्रा की सभी वस्तु उपलब्ध थी।

फिलहाल डिप्टी कमिश्नर लापता है। 25 जुलाई को जबलपुर में पूछताछ के बाद सरवटे को उनके घर छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला है। उनका मोबाइल बंद है और वह अब तक पेश नहीं हुए हैं। यदि आगे भी वे नहीं आते हैं, तो ईओडब्ल्यू उन्हें कानूनी नोटिस जारी करेगी।

भोपाल में 45 लाख का फ्लैट- ईओडब्ल्यू के मुताबिक भोपाल के मिसरौदा थाना अंतर्गत नर्मदापुरम रोड पर स्थिति जगदीश सरबटे के फ्लैट की कीमत करीब 40 से 42 लाख रुपए बताई जा रही है। सरवटे ने 2021 में इस फ्लैट को खरीदने के बाद अक्सर यहां पर आकर रुका करता था। जब कभी भी विभागीय काम इसका होता था तो भोपाल में रुकने के दौरान अपने दोस्तों के साथ यह इसी फ्लैट पर रात गुजारा करता था। ईओडब्ल्यूकी टीम को फ्लैट से कई बैंक पासबुक भी मिली है, जिसका पहले मिली पासबुक से मिलान किया जाएगा।

बांधवगढ़ में आलीशान रिसॉर्ट- एक हफ्ते पहले जबलपुर और सागर में हुई छापेमारी के दौरान सरवटे की करोड़ों की संपत्तियों का पता चला। जबलपुर के आधारताल और रामपुर स्थित घरों से नकदी, महंगी शराब, बाघ की खाल, बैंक दस्तावेज़ और सोने-चांदी के जेवर मिले। इसके अलावा, बांधवगढ़ में उनका आलीशान रिसॉर्ट और मंडला में हाईवे किनारे जायका नाम का ढाबा भी मिला।

अब तक 12 करोड़ की संपत्ति का खुलासा- अब तक की जांच में सरवटे की करीब रू. 12 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है, जिसमें भोपाल, जबलपुर, सागर, मंडला और बांधवगढ़ की संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, कई जमीनों के दस्तावेज़ मिले।

56 बोतल महंगी शराब (मूल्य 1 लाख से अधिक)

10 बैंक खातों में भारी लेनदेन
निर्माणाधीन रिसॉर्ट और दुकानें
होटल और मकान भी पाए गए हैं।

भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में बारिश, राजगढ़ में बाढ़ जैसे हालात

भिंड की सिंध नदी में बहे युवक की मौत, पुजारी का रेस्क्यू, शिवपुरी में सड़क पर आए मगरमच्छ

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार तो कई जिलों में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन में सोमवार सुबह से ही रुक-रुककर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। लगातार बारिश से नर्मदा समेत प्रदेश की प्रमुख नदियां उफान पर हैं।

राजगढ़ जिले में भी तेज बारिश दौर जारी है। जिले के खिलचीपुर और ब्यावरा में कई इलाकों में पानी भर गया है। नीमच में भी नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से नीमच-कोटा स्टेट हाईवे बंद हो गया है।

मौसम विभाग ने ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में सोमवार की सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भोपाल में हल्की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। देर शाम तक भोपाल में झमाझम बारिश होती रही।

राजगढ़ के खिलचीपुर में गाडगंगा नदी उफान पर है। जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। घरों-दुकानों में पानी घुस गया है। सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया।

राजगढ़ जिले के ब्यावरा में भी लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। यहां सोमवार को घुरेल का मार्ग नाले में पानी बढ़ने के कारण बंद हो गया। इससे यहां आवाजाही बंद हो गई। नीमच जिले के सिंगोली की ब्राह्मणी व ताल नदी उफान पर है। इससे नीमच-कोटा स्टेट हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। शिवपुरी के सिद्धेश्वर मंदिर मार्ग पर रविवार रात को नाले पर बनी पुलिया पर दो मगरमच्छ खुलेआम घूमते दिखाई दिए। एक राहगीर ने इनका वीडियो बना लिया। मंदसौर जिले के भानपुरा में बड़े महादेव के झरने पर प्रतिबंध के बावजूद लोग जोखिम लेकर फोटो खिंचवाते और रील बनाते नजर आए। शाजापुर में सुबह से रुक-रुककर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है।

सिंध नदी खतरे के निशान से ऊपर, बहने से युवक की मौत- भिंड में सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान से ऊपर आ गई है। सिंध नदी के पानी ने रौन क्षेत्र के इंदुर्खी गांव के एक पुरा को घेर लिया। पुलिया पर दस फीट पानी आने से एक युवक बह गया जिससे उसकी मौत हो गई। इधर बिलाव गांव के नजदीक पानी आने से मंदिर का पुजारी पानी में फंस गया।

खिलचीपुर- कलेक्टर-एसपी ने लिया हालात का जायजा

खिलचीपुर में जलभराव की सूचना मिलने पर सोमवार सुबह तहसीलदार और नगर परिषद सीएमओ अनिल जोशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेसीबी मशीन से सड़क की तरफ गड्ढा खोदकर पानी की निकासी करवाई। तब जाकर सड़कों से पानी निकलना शुरू हुआ। हालात का जायजा लेने दोपहर करीब 12:15 बजे कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी अमित तोलानी भी खिलचीपुर पहुंचे। उन्होंने अफसरों के साथ गाडगंगा नदी, इमली स्टैंड और छापीहेड़ा नाके का निरीक्षण किया।

राजगढ़, गाडगंगा नदी उफान पर, घरों-दुकानों में घुसा पानी

राजगढ़ जिले में पिछले दो दिनों से जारी लगातार बारिश से खिलचीपुर शहर के हालात बिगड़ गए हैं। गाडगंगा नदी उफान पर है। जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। छापीहेड़ा रोड, इमली स्टैंड, खांडी बावड़ी रोड सहित कई सड़कों पर तीन फीट तक पानी भर गया। सड़कों का हाल ऐसा हो गया कि वे तालाब में तब्दील नजर आने लगीं और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। वाहन चालकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश के पानी की निकासी न होने से छापीहेड़ा नाके पर रहने वाले पवन मालाकार के घर के अंदर पानी भर गया।

रोग की पहचान, फॉलोअप और समय पर सही उपचार महत्वपूर्ण : उप मुख्यमंत्री

- पीडियाट्रिक कैंसर के प्रभावी प्रबंधन के लिए 'कैनकिड्स' संस्था से सहयोग पर हुआ विचार विमर्श

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रोग की पहचान, उसका फॉलोअप और समय पर सही इलाज उपलब्ध होना, रोग के निदान के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं। सशक्तिकरण स्वास्थ्य तंत्र के लिए इन सभी घटकों पर आपसी समन्वय से कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कैंसर पीड़ित बच्चों को उन्नत इलाज और सामाजिक सहयोग की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सोमवार को मंत्रालय भोपाल में पीडियाट्रिक कैंसर के बेहतर प्रबंधन के लिए कैनकिड्स संस्था से सहयोग के विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार पीडियाट्रिक कैंसर की चुनौती से निपटने के लिए एकीकृत रणनीति पर कार्य

करेगी, जिसमें शासन, विशेषज्ञ संस्थाएं और समाज की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। राज्य में उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञों के बेहतर उपयोग के लिए हब-स्पोक्स और रेफरल पाथवे मॉडल को अनुमोदित कर चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। मानव संसाधन जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सामाजिक सहयोग टीमों की क्षमता वृद्धि और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कैनकिड्स संस्था से इस सहयोग के लिए अपने सुझाव देने का आग्रह किया।

बैठक में पीडियाट्रिक कैंसर की देखरेख के लिए उपयुक्त अधोसंरचना के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण के विभिन्न विषयों पर विमर्श

भाजपा विधायक बोले- सारी सड़कें वाटर पार्क हो गईं ?

- प्रीतम लोधी ने कहा- दिग्विजय के समय सड़कें ओम पुरी जैसी थी, हमने श्रीदेवी जैसी बनाई

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में बारिश के मौसम में सड़कों की बिगड़ी हालत को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इसे लेकर विपक्ष

लगातार सरकार की घेराबंदी में जुटा है। वहीं सत्ताधारी दल के विधायक प्रीतम लोधी ने इस पर अजीब बयान दिया है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के समय सड़कें ओम पुरी जैसी हुआ करती थीं। अब हमारे समय में तो सड़कें श्रीदेवी जैसी कर दी हैं। लेकिन, अभी पानी गिर रहा है। अभी इंद्र भगवान से समझौता होना है।

शिवपुरी के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेने भोपाल पहुंचे थे। मीडिया ने खराब सड़कों को लेकर उनसे सवाल किया था।

सारी सड़कें वाटर वार्क हो गई हैं- बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी प्राइवेट कैब से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा ओला कैब से आने का एक ही कारण है कि इंद्र भगवान नाराज चल रहे हैं। बहुत पानी बरसा रहे हैं। सारी सड़कें वाटर पार्क हो गई हैं। हमारे पास नाव तो है नहीं, तैर कर नहीं आ सकते। मेरे पास छोटी गाड़ी थी इसलिए उस छोटी गाड़ी से नहीं आ सके तो हमने ओला गाड़ी कर ली।

प्रीतम ने कहा था- देश में चलेगा मोदी-लोधी सिक्का- भाजपा विधायक प्रीतम लोधी पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। करीब 2 महीने पहले जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने कहा था कि देश में मोदी और लोधी का सिक्का चलेगा। जातिगत जनगणना से ओबीसी समाज का बहुत भला होने वाला है। ओबीसी समाज इससे उभर कर आएगा।

प्रीतम लोधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना के फैसले से मोदी जी ने लोधी समाज का तो बहुत बड़ा उद्धार कर दिया है। मप्र में 40 और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोधी बाहुल्य हैं। यूपी में 80 और मप्र में 40 विधायक बन सकते हैं।

सरकारों में भागीदारी बन सकती है, तो लोधी एंड मोदी बन

दिव्यांगता परमात्मा का परम अंश और इनकी सेवा परमात्मा की सेवा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

दिव्यांगजन को जरूरत के मुताबिक लाभ दिलाएं

सीएम ने की सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सामाजिक समानता और समरसता लोक कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक दायित्व है। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर दिव्यांगजनों और कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ति एवं उनका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार दिव्यांगजनों को संबल देकर उन्हें समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दिव्यांगजन परमात्मा का परम अंश है और इनकी सेवा परमात्मा की सेवा है। दिव्यांगजनों को लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाएं। इन शिविरों में नए दिव्यांगजनों को भी चिन्हित किया जाए और उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक सहयोग, मार्गदर्शन तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए योजना कियान्वयन की सतत् निगरानी भी सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांगजनों के विकास एवं कल्याण के लिए अब तक हुए प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

नवनिर्मित पेड ओल्ड एज होम का लोकार्पण बहुत जल्द

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेड ओल्ड एज होम आज के दौर में वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत बनते जा रहे हैं। नए परिवेश में बच्चे पढ़ने या नौकरी के लिए विदेश/बाहर चले जाते हैं। आगरा और जयपुर जैसे शहरों में पेड ओल्ड एज होम अच्छी तरह से संचालित हैं। इस तरह के वृद्धाश्रमों के लिए भारतीय परिवेश और संस्कृति से जुड़ा कोई हिन्दी नाम तय कर इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की देख-रेख सेवा का काम है इस काम से अशासकीय संगठनों और धार्मिक व परमार्थ संस्थाओं को भी जोड़ें।

मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि भोपाल के पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र में कुल 23.96 करोड़ रुपए की लागत से एक शासकीय पेड ओल्ड एज होम का निर्माण कराया गया है। इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण बहुत जल्द मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कर कमलों से ही कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नवनिर्मित पेड ओल्ड एज होम में सेवाएं देने के लिए इच्छुक संस्था के चयन के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसका संचालन यहां निवासरत वरिष्ठजनों से समुचित शुल्क लेकर किया जाएगा। इस वृद्धाश्रम के कमरों का किराया सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बैंकखाते में जमा कराया जाएगा।

विशिष्ट पहचान पत्र और पेंशन भुगतान में उल्लेखनीय प्रगति

मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि प्रदेश में अबतक 9.57 लाख से अधिक दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड (विशिष्ट पहचान पत्र) बनाए जा चुके हैं। इन पहचान पत्रों के आधार पर दिव्यांगजन शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 56 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को हर माह 339 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के जरिए उनके बैंकखातों में हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2500 से अधिक दिव्यांगजनों को शासकीय सेवा में रोजगार प्रदान किया गया है। मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बीते 10 सालों में कुल 11294 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ जनों के उपचार के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है इन केन्द्रों में फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ही अन्य प्रकार की थैरेपेटिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

नि:शुल्क दिव्यांग हेल्पलाइन 1800-233-4397 शुरु- बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती वायंगणकर ने बताया कि प्रदेश में श्रवण बाधित दिव्यांगजनों की सहायता के लिए लाइव इंटरप्रेटर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। इसके लिए 'डेफ कैन एसोसिएशन' संगठन के साथ एमओयू किया गया है।

मध्यप्रदेश में पर्यवेक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में

चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन की तिथियाँ घोषित

भोपाल में 4 से 7 अगस्त तक होगा दस्तावेज़ परीक्षण कार्यक्रम

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा आयोजित पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की मेरिट सूची अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। महिला एवं बाल विकास द्वारा चयनित प्रतिभागियों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण 4 से 7 अगस्त तक भोपाल स्थित संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, विजया राजे वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स में किया जाएगा।

दस्तावेज़ सत्यापन कार्यक्रम को दो भागों - सीमित सीधी भर्ती और खुली सीधी भर्ती के तहत विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 560 चयनित प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है। सीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 4 और 5 अगस्त को होगी। 4 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनारक्षित श्रेणी के 87 अभ्यर्थियों का और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक अनुसूचित जाति वर्ग के 54 अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त को पूर्वाह्न में 69 अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा, जबकि अपराह्न में 47 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और 32 ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ परीक्षण किया जाएगा। इस श्रेणी में कुल 289 अभ्यर्थी शामिल हैं।

खुली सीधी भर्ती के तहत दस्तावेज़ परीक्षण 6 और 7 अगस्त को किया जाएगा। 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक अनारक्षित वर्ग के 87 तथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक अनुसूचित जाति वर्ग के 49 अभ्यर्थियों का सत्यापन निर्धारित है। इसी तरह 7 अगस्त को पूर्वाह्न में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 62 अभ्यर्थियों और अपराह्न में 44 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 29 ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों का परीक्षण होगा। इस श्रेणी में कुल 271 अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं।

चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर दस्तावेजों की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति सेट सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। दस्तावेज़ों में मुख्यतः मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (एसडीएम द्वारा जारी), 10वीं एवं 12वीं की अंकसूचियाँ (स्नातक की हो तो उसकी भी), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र, उपस्थिति पत्रक, निःशक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, संविदा नियुक्ति एवं अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की मूल प्रति (जिससे लिंक मोबाइल साथ लाना अनिवार्य है), ईएसबी परीक्षा परिणाम की प्रति एवं ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र शामिल हैं।

दस्तावेज़ सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को पर्यवेक्षक पद के लिये नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के दावे पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।

- नई शिक्षा नीति से रोजगार और कौशल विकास में बढ़ेंगी संभावना

मॉडल स्कूल छात्रसंघ का शपथ समारोह

भोपाल (नप्र)। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि देश में वर्ष 2014 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति-2020 है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का शिक्षा के क्षेत्र में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय है। नई शिक्षा नीति से स्कूल में बच्चों का कौशल विकास और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जहां नई शिक्षा नीति को निरंतर प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। मंत्री श्री सिंह सोमवार को भोपाल के मॉडल स्कूल टीटी नगर छात्र संघ के शपथ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री सिंह ने इस मौके पर प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया। इन बच्चों ने बोर्ड की कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किये हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने प्रदेश के स्कूलों की गुणवत्ता की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में 75 हजार स्कूल मॉडल, एक्सीलेंस और पीएमश्री के रूप में सर्व-सुविधा के साथ विकसित किये जा चुके हैं। बच्चों को विश्व-स्तरीय अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये करीब 300 स्कूल सांदीपनि विद्यालय के रूप में संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रतलाम के सांदीपनि स्कूल ने तो दुनिया के श्रेष्ठ स्कूलों में अपना स्थान बनाया है। यह मध्यप्रदेश के लिये गौरव की बात है।

डिजिटल अटेंडेंस

स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था शिक्षकों के लिये भी सुविधाजनक है। शिक्षक डिजिटल प्लेटफार्म से अपने अवकाश की स्वीकृति, लेखा संबंधी और समस्याओं को भी दर्ज करा सकते हैं। इस डिजिटल प्लेटफार्म को भोपाल के कमांड सेंटर से संचालित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही अनुकंपा नियुक्ति नीति भी घोषित करेगा। इसके माध्यम से एक निश्चित समय-सीमा में दिवंगत शिक्षकों के परिवार के नियुक्ति संबंधी प्रकरणों को हल किया जायेगा। कार्यक्रम को विधायक श्री भगवान दास सबनानी ने भी संबोधित किया। मॉडल स्कूल की प्राचार्य श्रीमती रेखा शर्मा ने गुणवत्ता के क्षेत्र में स्कूल को प्राप्त श्रेष्ठ पुरस्कारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छात्रसंघ के चुनाव के जरिये बच्चों को चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। बच्चों ने इस मौके पर देश की विविधता भरी संस्कृति पर केन्द्रित आकर्षक सामूहिक नृत्यों को प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में क्षेत्र की पार्षद श्रीमती अनीता अनेजा, उप प्राचार्य श्री आर.के. श्रीवास्तव, शिक्षकगण और परिजन भी मौजूद थे।

जनजातीय संग्रहालय में होगा निदा फाजली को समर्पित याद ए रफ्तगाँ

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिसर और संस्कृति विभाग द्वारा प्रख्यात शायर पदमश्री निदा फाजली को समर्पित याद ए रफ्तगाँ संगोष्ठी का 29 जुलाई को सायं 5 :30 बजे जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में आयोजन होगा। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक और धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उर्दू अकादमी के निदेशक डॉ. नुसरत मेहदी ने बताया कि कार्यक्रम में मै निदा निदा फाजली पर श्री अतुल गंगवार द्वारा सम्प्रेषण एवं श्री अदबी कॉकटेल द्वारा निर्मित डाक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम 3 सत्रों पर आधारित होगा। आयोजन में मालती जोशी मुंबई, शकील आजमी मुंबई, अतुल पांडेय निदेशक, आलोक श्रीवास्तव दिल्ली सहभागिता करेंगे। अंतिम सत्र में काव्य पाठ का आयोजन होगा जिसमें शकील आजमी मुंबई एवं आलोक श्रीवास्तव दिल्ली अपना कलाम पेश करेंगे।

भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर टॉप टेन बेरोजगार जिले

25.68 लाख युवा बेरोजगार, सात माह में 48624 युवाओं के घटने का दावा

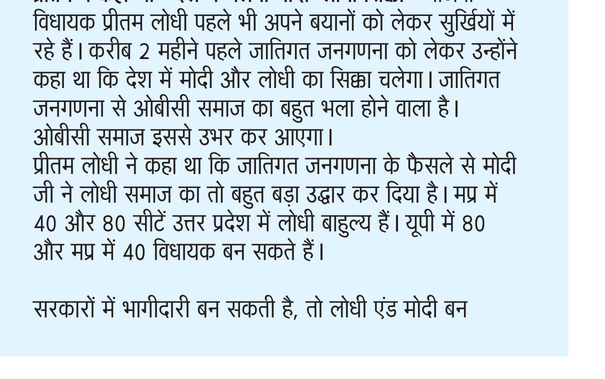

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में 25 लाख 68 हजार युवा बेरोजगार हैं जिन्हें रोजगार की तलाश है। बेरोजगारों के पंजीयन के लिए बनाए गए रोजगार पोर्टल में आकांक्षी युवा के रूप में इन युवाओं के नाम हैं। दूसरी ओर सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में 0.56 प्रतिशत की कमी आई है। यह संख्या सात माह पहले जारी किए गए बेरोजगारों के आंकड़े से 48624 कम है। दो वर्षों में मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल पर 15 लाख 38 हजार 837 आकांक्षी युवा रजिस्टर किए गए हैं। बेरोजगार युवाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर सागर जिला और सबसे नीचे पांढुर्णा है। प्रदेश के 21 जिले ऐसे हैं जहां बेरोजगार युवाओं की संख्या 50 हजार के पार है। वहीं 34 जिलों में यह संख्या 50 हजार से कम है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा जबलपुर, ग्वालियर बेरोजगार युवाओं की संख्या के मामले में टॉप टेन जिलों में शामिल है। साथ ही विंध्य के रीवा संभाग के तीन जिले रीवा, सतना और सीधी भी टॉप टेन बेरोजगारी वाले जिलों में शामिल हैं।

संजय उइके और आतिफ अकील ने मांगी जानकारी- विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधायक संजय उइके और आतिफ अकील ने प्रदेश में बेरोजगारों को लेकर राज्य सरकार से अलग-अलग जानकारी मांगी। सरकार ने पंजीयन में इन युवाओं को बेरोजगार के बजाय आकांक्षी युवा के रूप में रोजगार पोर्टल में रजिस्टर किया है। इसलिए विधायकों ने आकांक्षी युवाओं की जिला वार जानकारी मांगी जिसके लिखित जवाब में कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि पूर्व के मुकाबले इसमें 0.56 प्रतिशत की कमी आई है।

सात माह पहले बढ़े थे 35186 बेरोजगार- राज्य सरकार ने सात माह पहले दिसम्बर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जो जानकारी दी थी, उसमें पूर्व में दी गई बेरोजगारों की संख्या के मुकाबले बेरोजगार घटने की बजाय बढ़ गए थे। दिसम्बर में सरकार के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई थी कि मध्यप्रदेश में पांच माह में 35186 बेरोजगार बढ़ गए। मई 2024 में सरकार ने विधानसभा में बेरोजगारों की संख्या 25 लाख 82 हजार 759 बताई थी। तब प्रदेश में 7.58 लाख बेरोजगार घटे थे।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह का नया रिकार्ड

- यूनिट नंबर 5 ने लगातार दूसरी बार बनाया 300 दिन विद्युत उत्पादन करने का नया रिकॉर्ड

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई के अभियंताओं व कार्मिकों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता ने 210 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट को लगातार 300 दिन तक संचालित करने में सफलता हासिल की है। यूनिट ने अपनी स्थापना के बाद दूसरी बार 300 दिन विद्युत उत्पादन करने का रिकार्ड बनाया। इस यूनिट ने दूसरी बार 1 अक्टूबर 2024 से 28 जुलाई 2025 तक 300 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने का रिकार्ड बनाया। इससे पूर्व इस यूनिट ने 27 अगस्त 2023 से 22 जून 2024 तक 300 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने का नया रिकार्ड बनाया था। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अमरकंटक ताप विद्युत गृह के यूनिट नंबर 5 के अभियंताओं व कार्मिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि समर्पण, कड़ी मेहनत व प्रतिबद्धता से लक्ष्य अर्जित करने का यह सर्वश्रेष्ठ व अनुकरणीय उदाहरण है।

सारनी की यूनिट नंबर 10 के नाम दर्ज है सर्वाधिक 305 दिन सतत् विद्युत उत्पादन

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन माफी पर विजय शाह को फटकारा

कहा- सार्वजनिक माफी कहां है? हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे एसआईटी 13 को जवाब देगी

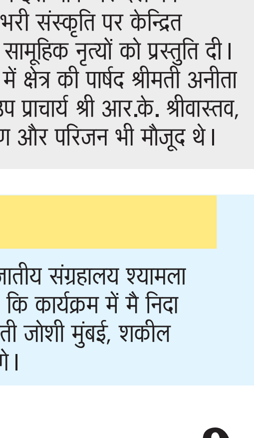

नईदिल्ली/भोपाल (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा मंत्री विजय शाह की ऑनलाइन माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने शाह के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से मांगी गई माफी को निष्ठाहीन बताते हुए खारिज कर दिया। यह देखते हुए कि अपने माफीनामे वाले वीडियो में शाह ने जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात स्वीकार नहीं की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- वह आत्मचिंतन करें कि अपनी सजा कैसे चुकाएं। आपकी वह सार्वजनिक माफी कहां है? हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होंगे शामिल

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 जुलाई मंगलवार को दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में 'अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस' के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर वन्य जीव ट्रांस लोकेशन, रेस्क्यू एवं डॉग स्क्वॉड वाहनों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव वन्य जीव संरक्षण गतिविधियों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन कर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा समितियों, ईको विकास समिति, ग्राम वन समिति और वन कर्मियों को पुरस्कृत भी करेंगे।

संपादकीय

ट्रेन का खाना, रेल मंत्री के दावे!

भारतीय रेलवे चलती ट्रेन में परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी और हाइजीन को लेकर चाहे जितने दावे करे, हकीकत यही है कि न तो रेल यात्री इससे संतुष्ट हैं और न ही यह अपेक्षित गुणवत्ता का होता है। ट्रेन में सर्व किए जाने वाले खाने की रेलवे को मिली शिकायतों के आंकड़ों से यह बात सिद्ध होती है। कई मामलों में कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन यात्रियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद नहीं हो रहा। यह बात रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा संसद में दिए उनके जवाब से स्पष्ट होती है। ट्रेनो में खराब खाने के बारे में माकपा सांसद सांसद जॉन ब्रिटास ने रेल मंत्री से जानकारी चाही थी। उन्होंने ट्रेनों में खाने की क्वालिटी और कंपनियों को ठेके देने में पारदर्शिता से जुड़ा सवाल पूछा था। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जवाब दिया कि साल 2024-25 के दौरान खाने की क्वालिटी को लेकर 6 हजार 645 शिकायतें मिलीं। इसी साल 1 हजार 341 मामलों में भोजन की सप्लाई करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। रेल मंत्री ने बताया कि साल 2023-24 में 7 हजार 026 शिकायतें मिली थीं जबकि 2022-23 में 4 हजार 421 शिकायतें आई थीं। वहीं साल 2021-22 में खाने की खराब क्वालिटी की 1 हजार 82 शिकायतें दर्ज की गई थीं। रेल मंत्री ने बताया कि कुल शिकायतों में से 2 हजार 995 मामलों में कैटरिंग ठेकेदार को चेतावनी दी गई। 547 मामलों में उन्हें उचित सलाह दी गई और बाकी बचे 762 मामलों में दूसरे कदम उठाए गए। माकपा सांसद ने यह भी पूछा था कि क्या रेलवे कैटरिंग ठेकेदारों से अनहाइजेनिक तरीके से तैयार भोजन को जब्त किया गया है? इस पर वैष्णव ने बताया अगर खाने में मिलावट या अस्वच्छता पाई जाती है या यात्री शिकायत करते हैं, तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसमें जुर्माना लगाना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, काउंसलिंग करना और चेतावनी देना शामिल है। सांसद ब्रिटास का एक और सवाल था कि क्या आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) ने कई रेलवे रूटों पर, जिसमें वंदे भारत और दूसरी लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हैं, एक ही कंपनी समूह को अलग-अलग नामों से ठेके दिए हैं? इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईआरसीटीसी ट्रेनों में खानपान सेवाएं देने के लिए समय-समय पर टेंडर निकालती है। इसी क्रम में वंदे भारत और लंबी दूरी की दूसरी ट्रेनों के लिए भी टेंडर निकाले जाते हैं। टेंडर एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दिए जाते हैं। जो कंपनी या ठेकेदार सबसे ऊंची बोली लगाता है, उसे ही टेंडर मिलता है। यह सब टेंडर के नियमों और शर्तों के अनुसार ही होता है। रेल मंत्री का दावा था कि रेल में भोजन सप्लाई के मामले में विभाग की पूरी नजर रहती है। रेल प्रशासन भोजन की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाता है। उन्होंने बताया कि चलती रेलगाड़ी में भोजन नहीं बनाया जाता है बल्कि उसे बेस किचन में तैयार कर ट्रेन में सप्लाई किया जाता है। इस समय ठेकेदारों के बेस किचन आधुनिक बनाए जा रहे हैं। क्वालिटी पर नजर रखने के लिए बेस किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भोजन तैयार करने के दौरान भी अच्छी क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। इस दौरान फूड सेफ्टी सुपरवाइजर वहां साफ-सफाई का ध्यान तो रखते ही हैं, वे भोजन पकाने की प्रक्रिया पर भी नजर रखते हैं। रेल मंत्री जो भी दावे करें, वास्तव में रेलवे का भोजन यात्री मजबूरी में ही खाते हैं। इनमें ज्यादातर वो होते हैं, जो या तो निरंतर प्रवास करते हैं या फिर वो, जो किसी कारणवश घर का खाना नहीं ला सकते।

बदलते विश्व में भारत का दूरदर्शी निर्णय

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
लेखक स्तंभकार हैं।

कूटनीति और व्यापार के क्षेत्र में जब विश्व के बड़े राष्ट्र अपनी संकीर्णता और संरक्षणवाद की संकीर्ण गलियों में सिमट रहे हैं, तब भारत ने वैश्विक सहयोग और द्विपक्षीय साझेदारी की ऊंची राह पर अग्रसर होते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ब्रिटेन के साथ 'समग्र आर्थिक एवं व्यापार समझौता' (कॉम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट- सी ई टी ए) पर हस्ताक्षर कर एक ऐसा समझौता किया गया है, जिसे न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि रणनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी 'गेम चेंजर' माना जा रहा है। यह समझौता उस समय हुआ है जब वैश्विक व्यापारिक अस्थिरता, ट्रंप प्रशासन की उच्च टैरिफ नीति और ब्रेक्ज़िट के पश्चात ब्रिटेन की नई भू-राजनीतिक ज़रूरतें, सब कुछ पुनर्संयोजन की मांग कर रहे थे। ऐसे में यह डील भारत की दूरदर्शिता, वैश्विक नेतृत्व क्षमता और मजबूत नीति निर्धारण का प्रतीक बनकर उभरी है।

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते की रूपरेखा: नए दौर का द्वार

भारत और ब्रिटेन के बीच यह समझौता लगभग तीन वर्षों की कठिन वार्ताओं के बाद 2025 में संपन्न हुआ। इसे भारत का अब तक का सबसे समग्र (कंप्रेहेंसिव) और रणनीतिक व्यापारिक समझौता माना जा रहा है। वर्तमान में भारत-ब्रिटेन का कुल वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 21.34 बिलियन डॉलर (2023-24) का है, जिसे इस समझौते के माध्यम से 34 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और वर्ष 2030 तक 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह व्यापार वृद्धि दोनों देशों के लिए आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होगी। यह समझौता 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (एफटीए) की अवधारणा के अंतर्गत आता है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), डिजिटल ट्रेड, डेटा प्रवाह, श्रम गतिशीलता, और कानूनी विवाद समाधान जैसे विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। यह डील केवल वस्तु व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेवा क्षेत्र, कृषि उत्पाद, पेशेवर आवाजाही और तकनीकी सहयोग को भी एक नई ऊंचाई देती है।

व्यापार में वृद्धि और शुल्क में कमी: द्विपक्षीय लाभ का समुचित संतुलन

इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को ड्यूटी-फ्री (शून्य शुल्क) पहुंच मिलेगी, जिससे वस्त्र, रत्न-आभूषण, चमड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री खाद्य, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वर्तमान में जी डी पी में हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है, जबकि सरकार का लक्ष्य इसे 25 प्रतिशत तक ले जाना है। इसी प्रकार वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 2.8 प्रतिशत है जबकि चीन की 28.8 प्रतिशत है, ऐसे में यह डील भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मौजूदगी को सशक्त बनाएगी। ब्रिटेन की ओर से भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों पर लगने वाला 18 प्रतिशत का शुल्क अब हट जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में 2030 तक 7.5 बिलियन डॉलर के निर्यात की संभावना बन रही है। स्मार्टफोन, इन्वर्टर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑटो कलपुर्जे आदि उत्पाद अब बिना शुल्क ब्रिटेन भेजे जा सकेंगे।

फायदेमंद साबित होगा यह समझौता

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक उल्लेखनीय वरदान के रूप में सामने आया है। अब भारत के फल, सब्जियां, मसाले, चाय, बासमती चावल, हल्दी, मिर्च, गुड़, शहद और मछली जैसे कृषि उत्पाद ब्रिटेन के प्रीमियम बाजारों तक बिना शुल्क पहुंच सकेंगे, जबकि पहले इन पर 10-20 प्रतिशत तक शुल्क लगता था। फेनी (गोवा), ताड़ी (केरल) और वाइन (नासिक) जैसे उत्पादों को जी आई टैग के साथ वहां की बाजार में विशेष पहचान मिलेगी, जिससे राज्यों के स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह समझौता भारत को ब्रिटेन में निर्यात की सुविधा प्रदान करता है तो वहीं ब्रिटेन को भारत जैसे विशाल और उभरते उपभोक्ता बाजार तक अधिक सहज पहुंच मिलती है। ब्रिटेन से कारें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डेयरी उत्पाद, मेडिकल डिवाइस आदि अब भारत में कम शुल्क पर उपलब्ध हो सकेंगे।

इस समझौते से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नए द्वार खुलेंगे। खासकर ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश निवेश से 'मेक इन इंडिया' और 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन' को बल मिलेगा। इसके साथ ही एम एस एम ई और स्टार्टअप सेक्टर के लिए ब्रिटेन जैसे उच्च क्रय शक्ति वाले बाजारों तक पहुंच का रास्ता खुलेगा, विशेषकर फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थ-टेक और एजु-टेक में वैश्विक साझेदारियाँ बनने की संभावना है। भारत की महिला उद्यमिता और युवा नेतृत्व को ब्रिटिश बाजार, संसाधन और निवेश नेटवर्क तक पहुंच का विशेष अवसर मिलेगा।

समझौते की व्यापकता इसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़ी ग्रीन टेक्नोलॉजी, कार्बन क्रेडिट, और सतत आपूर्ति श्रृंखला जैसी अवधारणाओं के समावेश से भी स्पष्ट होती है। लाइफ मिशन 'LIFE Mission' और ब्रिटेन की हरित नीति के समन्वय से सतत विकास को नई दिशा मिल सकती है। इसके अतिरिक्त डिग्री मान्यता, रिसर्च साझेदारी और वर्क परमिट सुविधाओं से दोनों देशों के युवाओं, शोधार्थियों और पेशेवरों को लाभ होगा। सेवा क्षेत्र में योग, संगीत, पाक कला, अकाउंटेंसी आदि के पेशेवरों को ब्रिटेन के उच्च-मूल्य बाजार में जगह मिलने से भारत की सॉफ्ट पावर और प्रतिभा को वैश्विक मंच मिलेगा। डबल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के अंतर्गत अब भारतीय पेशेवरों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा नहीं चुकानी पड़ेगी, जिससे लाखों डॉलर की बचत होगी।

वैश्विक व्यापार में भारत की रणनीतिक बढ़त

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता मात्र एक व्यापारिक अनुबंध नहीं है, बल्कि यह भारत की उस दूरदर्शी नीति का जीवंत प्रतिबिंब है, जिसके अंतर्गत भारत अपने आप को एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व मंच पर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यह अनुबंध न केवल आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह भारत की उन रणनीतिक पहलों का भी प्रतीक है, जिनका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में समावेशन और स्थायित्व को सुनिश्चित करना है। 2014 के पश्चात, भारत ने मॉरिशस, यू ए ई, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के साथ फ्री ट्रेड डील्स को अंतिम रूप दिया है, जिसने देश के निर्यात-आयात तंत्र को नयी दिशा दी है और आर्थिक विकास के नए आयाम खोले हैं। इसी क्रम में, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के साथ भी बारंबार बातचीत प्रगति पर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का दृष्टिकोण न केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित है, बल्कि यह व्यापक वैश्विक सहयोग के नेटवर्क का हिस्सा बनने की आकांक्षा रखता है।

भारत का यह समग्र दृष्टिकोण न केवल अपने घरेलू बाजार को सशक्त बनाने के लिए है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश, तकनीकी सहयोग, और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी को मजबूती प्रदान करते हुए, भारत ने एक ऐसा मंच तैयार किया है, जिस पर उसका विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का सपना धीरे-धीरे साकार होता दिखाई देता है। यह समझौता और इसके आगे भी निरंतर चल रहे व्यापारिक संवाद, भारत की आर्थिक नीतियों में परिवर्तनशीलता और नवाचार की प्रेरणा का प्रमाण हैं।

इस समझौते से भारत का बढ़ेगा दुनिया में साख

यह न केवल दो राष्ट्रों के बीच व्यापारिक लेन-देन को आसान बनाएगा, बल्कि भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, विशेषकर ऐसे समय में जब चीन की आक्रामक रणनीति और अमेरिका की अनिश्चित विदेश नीति से वैश्विक अस्थिरता बढ़ी है। भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ सामूहिक रणनीति विकसित करने के लिए भारत-ब्रिटेन साझेदारी उपयोगी हो सकती है। साथ ही, दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र, जी20, और कॉमनवेल्थ में समन्वित दृष्टिकोण के साथ वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी हस्तक्षेप कर सकते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान आरंभ हुई और अब वैश्विक स्तर पर व्यापक होती जा रही अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियाँ विश्व व्यापार के स्वरूप को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे माहौल में भारत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह किसी भी प्रकार के दबाव में व्यापार समझौते नहीं करेगा, बल्कि वैकल्पिक मार्गों और बहुपक्षीय रणनीति के तहत अपने हितों की रक्षा करता रहेगा। ब्रिटेन के साथ संपन्न हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता इसी नीति का ठोस उदाहरण है, जो भारत की न केवल आर्थिक परिपक्वता, बल्कि उसकी कूटनीतिक सूझबूझ को भी दर्शाता है।

तीन वर्षों के जटिल और व्यापक वार्तालाप के पश्चात यह समझौता साकार हुआ है। इस प्रक्रिया में बार-बार परिवर्तन हुए, प्राथमिकताएँ तय हुईं, और कई बार असहमति के बिंदु उभरे। बावजूद इसके भारत ने अपने रुख में न तो लचीलापन दिखाया और न ही जल्दीबाज़ी की। भारत ने यह साफ़ कर दिया कि वह किसी भी डेडलाइन या भूराजनैतिक दबाव के अधीन आकर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका की ओर से बार-बार भारत पर समय-सीमा निर्धारित कर दबाव बनाया गया कि वह उनके साथ भी व्यापार समझौता जल्द करे, किंतु भारत ने स्पष्ट किया कि उसके लिए प्राथमिकता 'गुणवत्ता आधारित समझौता' है, न कि 'समयबद्ध समझौता'। ब्रिटेन के साथ हुए इस समझौते के जरिये भारत ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन (E) सहित अन्य शक्तिशाली वैश्विक साझेदारों को यह संदेश दिया है कि वह अपनी संप्रभु नीतियों, रणनीतिक प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही, यह समझौता बहुपक्षीयता को प्राथमिकता देने की भारत की नीति को मजबूती प्रदान करता है, जिसमें किसी एक महाशक्ति पर निर्भर रहने की बजाय संतुलित वैश्विक भागीदारी को प्रमुखता दी जाती है।

आर्थिक समृद्धि की साझा यात्रा

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक अनिश्चितताओं, संरक्षणवाद और टैरिफ युद्धों के इस युग में आशा, सहयोग और समृद्धि की एक नई कथा लिखता है। यह केवल दो देशों के बीच हुआ व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि यह उन करोड़ों युवाओं, किसानों, उद्यमियों और पेशेवरों के लिए नए अवसरों का द्वार है जो भारत के भविष्य की नींव हैं। यह समझौता भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'लोकल से ग्लोबल' जैसी पहलों को गति देगा, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और वैश्विक मंच पर भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और निर्णायक राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा।

इस समझौते ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि भारत अब वैश्विक व्यापार की शर्तों को केवल स्वीकार नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने हितों के अनुसार गढ़ता भी है। यही भारत की उभरती शक्ति का प्रमाण है और यह डील उसी परिवर्तनशील भारत की आर्थिक कूटनीति की विजय गाथा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पांच वर्ष की उपलब्धियाँ

शिक्षा

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाँच वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। भारत मंडपम में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। अभी गुजरात में हुए कुलपति सम्मेलन हुआ। विविध विषयों पर विचार विमर्श हुए। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के तहत भारतीय भाषाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर ज्ञान को अधिक सहज, सुलभ और समावेशी बनाया जा रहा है। यह 'विकसित भारत' के निर्माण की दिशा में एक सार्थक व निर्णायक कदम विशेषज्ञ मान रहे हैं। बीते 5 वर्षों में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन मिला है। विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करें, इसका प्रयास हुआ है। निःसंदेह इससे उनकी समझ, अभिव्यक्ति, विश्लेषण और नवाचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। वास्तव में, जब शिक्षा अपनी भाषा में होती है, तब वह केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं रह जाती, अपितु सोचने और जीवन को संवारने वाली ऊर्जा बन जाती है। भारत सरकार का यह अध्याय निशंक जी ने 2020 में विशेष प्रयास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किया। अब उसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आगे बढ़ा रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए उठाए कदम निर्णायक भूमिका में अपनी उल्लेखनीय सेवा ऐतिहासिक रूप से अंकित करने लगे हैं जिसमें बहुत से इनिशिएटिव ऐसे हैं जो आने वाले समय में अपनी अभूतपूर्व विशेषताएं बताएँगे। यथा एनसीईआरटी द्वारा तैयार बुनियादी अध्ययन और स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम की रूपरेखा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की जा चुकी है। भारत में 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए पहली बार एकीकृत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाए गए स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 के अनुसार है। इसके तहत शैक्षणिक संरचना यानी आधारभूत चरण में 5 वर्ष, प्रारंभिक और मध्य चरण में 3-3 वर्ष और माध्यमिक चरण में 4 वर्ष शामिल है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षा 1 और 2 के लिए जुलाई, 2023 में और कक्षा 3 और 6 के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नई पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने स्कूलों को सलाह दी है कि वे पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को 21वीं सदी के कौशल के साथ एकीकृत करें। साथ ही, सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग और डेटा साइंस जैसे नए विषय भी शामिल किए हैं। पाठ्यक्रम भार को कम करने के लिए सीबीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए अपना पाठ्यक्रम कटौती कर कम सामग्री के साथ जारी किया था। इस शिक्षा नीति के तहत देश के 90 से अधिक विश्वविद्यालय ने एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में शुरू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति टेक्नॉलॉजी के लिए जरूरी माइंडसेट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसके लिए अटल टिकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क देश में तैयार किया जा रहा है और समग्र शिक्षा योजना 2.0 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप रि-डिजाइन किया गया है जो 2025-26 तक चालू रहेगी। यह इनिश्येटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के वे महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले हैं जिससे नई पीढ़ी विभिन्न लेयर में अपने आपको मजबूत करेगी और देश में एक नया परिदृश्य देखने को मिलेगा।

अब भारत का शिक्षा मंत्रालय बाल वाटिका, विद्या प्रवेश, निपुण भारत, पीएम ई विद्या, दीक्षा, स्वयंप्रभा, जादुई पिटारा, परख, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास। प्राइमर्स, निष्ठा, 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम व राष्ट्रीय मेटरिंग मिशन जैसी पहल करके भारत के हर आयु-वर्ग को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर चुका है। देश के शिक्षा तंत्र में बैठे लोगों का अब दायित्व क्या है, वे इसे किस प्रकार से अपने आसपास के जनमानस में अभिप्रेरण करते हैं और कैसे उन्हें इसमें सम्मिलित करते हैं, यह उन पर निर्भर है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संबोधन में कहा था कि 21वीं सदी के 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। भारत को नॉलेज इकोनॉमी के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में आप सबकी निर्णायक भूमिका है। शिक्षण के साथ-साथ शोधकार्य पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम आज किस प्रकार इस लक्ष्य को हासिल करें, यह सभी भारतीय शिक्षा जगत से जुड़े हितधारकों का दायित्व है।

अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि करते हुए इसे जीडीपी के 6 प्रतिशत तक पहुंचाने की स्पष्ट रूप से समर्थन एवं परिकल्पना की गई है। उसी दिशा में शिक्षा मंत्रालय सहित उससे जुड़े बजट में वृद्धि की जा रही है। यह बज़ट यद्यपि बहुत अधिक नहीं है। देश में शिक्षा की गुणवत्ता, शोध की गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा से समाज के निर्माण की यदि हम बात कर रहे हैं और यह विचार कर रहे हैं कि भारत इस दिशा में विकास करके एसडीजी-2030 लक्ष्य में भी अपनी विशेष उपस्थिति बनाए तो भारत के शिक्षा बज़ट को थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। हम हथियारों पर खर्च करें, शिक्षा पर अधिक तो यह देश के हित में होगा। हथियारों से युद्धक सामग्री खरीदी जा स्सक्ति है जो हमारी सुरक्षा के लिए अहम् हो सकती है लेकिन यदि यह बज़ट यदि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा हेतु बढाया जाएगा तो उससे हम भारत के भविष्य की सुरक्षा कर सकेंगे और यदि हम यह कहें की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो कहना है कि हम नॉलेज इकॉनोमी डेवलप करें तो हम इससे पीढ़ीगत भविष्य के साथ विजडम इकॉनोमी का उत्पाद अधिक कर सकेंगे।

भारत के सामने बहुत सी चुनौतियाँ हैं। शिक्षा में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। इसे भी चुनौती के रूप में भारत का बौद्धिक समाज लेगा तो निश्चय ही हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ न्याय कर सकेंगे। हमने एनईपी-2020 के साथ बहुत प्रयास भारत भर में किया है। अकादमिक जगत में इसको लेकर अभी कई धड़े बने हुए हैं जो एनईपी पर शक पैदा करते हैं। वे भी चुनौती हैं हमारे लिए व एनईपी के भविष्य के लिए। किन्तु सरकार की अपनी प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट है। वह इसे लेकर जिस गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ रही है। एनईपी के साथ भारत के लिए सरकार विजन 2047 के लिए भी काम कर रही है। इसलिए पांच वर्ष के हमारे कार्य को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता ज्यादा है। बजे इसके कि हम आगे-पीछे की सोचकर इसकी विकास यात्रा को अवरुद्ध करें या खुद इसको विकसित करने से कतराएँ।

विगत माह केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का दो दिवसीय सम्मेलन आज गुजरात के केवड़िया में हुआ। धर्मेंद्र प्रधान की पांच प्रतिज्ञाओं का स्मरण आता है। इस सम्मेलन में 50 से अधिक अग्रणी उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपतियों ने एनपीए 2020 के कार्यान्वयन पर ही विचार किया था। यह समागम ही समीक्षा, मूल्यांकन और रणनीति बनाने के लिए आयोजित हुआ था। इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पंच संकल्प की अवधारणा जिसमें सम्मिलित है अगली पीढ़ी की उभरती शिक्षा, बहु-विषयक शिक्षा, नवीन शिक्षा, समग्र शिक्षा और भारतीय शिक्षा, इस पर उच्च शिक्षाजगत के लोग एकजुट होकर काम करें। अब जब हम पांचवीं वर्षगाँठ पर पुनः सभी देश के लोग एक साथ सोचने विचारने के लिए एक दिवस पर एकात्मिक चिंतन कर रहे हैं तो हमें अपनी उपलब्धियों के साथ चुनौतियों पर भी सोचना है और भविष्य की योजनाओं को भी सजगता, धैर्य से आगे ले जाना है। यदि सभी एकजुट होंगे तभी सफलता मिलेगी क्योंकि सरकार केवल बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकती अकेले, बल्कि जब सभी स्टेकहोल्डर्स एक साथ एनईपी के लिए कार्य करेंगे तभी व्यापक उपलब्धियां मिल सकेंगी।

अफवाह के मनोविज्ञान पर चिंतन जरूरी

भगदड़ की घटनाएँ

ब्रजेश कानूनगो
लेखक स्तंभकार हैं।

हाल ही में जुलाई माह की 27 तारीख को हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में एक भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इस भगदड़ का कारण बिजली के करंट की अफवाह थी यद्यपि प्रारंभिक तौर पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने इसे खारिज कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। संकट के समय पीड़ितों की मदद करना एक अच्छा कदम अवश्य होता है, लेकिन ऐसे हादसे शासन, प्रशासन के अलावा प्रबुद्ध विचारकों और जागरूक नागरिकों को भी चिंतन करने को बाध्य करते हैं।

ऐसा नहीं है कि धार्मिक आयोजनों में भगदड़ का हादसा पहली बार हुआ हो। 2008 में हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भगदड़ में 146 लोगों की मौत हुई थी। 2010 में पश्चिम बंगाल के गंगासागर मेला में मकर संक्रांति के अवसर पर भगदड़ में कई लोगों की जान गई थी। 2013 में इलाहाबाद कुंभ मेले में भगदड़ में कई लोग घायल हुए थे। 2016 में पुत्तिंगल देवी मंदिर, केरल में आतिशबाजी के कारण हुए विस्फोट में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। अभी हाल ही में महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में भगदड़ की घटना 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के अवसर पर हुई, जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शाही स्नान के लिए उमड़ी। इस हादसे में कम से कम 38 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

धार्मिक स्थलों पर भीड़ और श्रद्धालुओं का उमड़ना और हादसे हो जाना एक आम समस्या हो गई है, जिसमें अक्सर सुरक्षा के अभाव में लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। इन हादसों में भगदड़ और अन्य दुर्घटनाएं शामिल हैं, किंतु सबसे पहले इनके पीछे किसी अफवाह का भीड़ में फैल जाना रहा है। ऐसा क्यों होता है?

यह अवश्य है कि अफवाहें एक प्रकार की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं जो अक्सर गलत सूचनाओं के प्रसार के रूप में सामने आता रहा है। अगर गौर करें तो जब लोगों को किसी खास स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, तो वे अफवाहों पर विश्वास करने लगते हैं। अनिश्चितता और भय के समय में अफवाहें और अधिक तेजी से फैलती हैं। दूसरी बात, लोग सामान्यतः अपने समूह या समुदाय में अन्यों से विशेष प्रभावित होते हैं। यदि एक समूह में कोई अफवाह फैलती है, तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। अक्सर अफवाहें मौखिक संचार के माध्यम से फैलती हैं। जब लोग एक-दूसरे से बात करते हैं, तो वे अक्सर जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर विकृत या अतिरंजित बनाकर आगे बढ़ाने लगते हैं और भीड़ में घबराहट बढ़ती जाती है।

ऐसा नहीं है कि ये अफवाहें वैसे ही फैलती जाती है, इसके पीछे कई अन्य घटक भी शामिल होते हैं। धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की कमी एक प्रमुख कारण है ही, जिसमें आयोजकों और प्रशासन की लापरवाही के कारण भगदड़ जैसी घटनाएं हो जाती हैं। आयोजनों में अव्यवस्था और लापरवाही के कारण भी हादसे होते हैं, उचित निकास मार्ग न होना और सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होना भी दुर्घटना के भयंकर स्वरूप का कारक बन जाते हैं। अफवाहों की तुरंत जांच करना और उन्हें सत्यापित करना भी बेहद महत्वपूर्ण कदम होता है। अन्य व्यवस्थाओं में उलझा प्रशासन विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने और तथ्यों की पुष्टि करने में कभी कभी चूक जाता है या वह इस कार्य में तनिक देर से सक्रिय हो पाता है। तब तक अफवाह अपनी आग फैला चुकी होती है। ऐसे में स्पष्ट और पारदर्शी संचार और सूचना तंत्र अफवाहों को फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। लोगों को सटीक जानकारी प्रदान करना और उन्हें अफवाहों के बारे में जागरूक करना भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन के इन उपायों के बावजूद भी यदि घटनाएं होती जा रही हैं तो निश्चित ही यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय हो जाता है।

जरूरी है कि अब इस दिशा में गंभीरता और प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना होगा। लोगों को अफवाहों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें सिखाना कि कैसे अफवाहों की पहचान करें और उनसे निपटें शायद एक प्रभावी तरीका हो सकता है। अफवाहों के मनोविज्ञान को उच्चतम बौद्धिकता से समझकर और संपूर्ण देश में व्यापक कदम उठाकर नकारात्मक प्रभावों को कम करने की कोशिश होना चाहिए। शायद तभी हम एक अधिक सूचित और जागरूक समाज का निर्माण कर सकते हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

भीड़ में भटकने का बहाना

व्यंग्य

केदार शर्मा
लेखक व्यंग्यकार हैं।

सावन-भादो के महीनों में पैदल यात्राओं का दौर शुरु हो जाता है। सुना है कि देवताओं की कतार में राहु-केतु ने अमृतपान कर लिया था। पैदल यात्राओं में भी वैसे ही मौज-मस्ती के चाहक श्रद्धालुओं के वेश में चलने लगे हैं। स्वागत सत्कार का जो 'अमृत' सब भक्तों को मिलता है, वही इन कम-भक्तों (कमबख्तों) को भी मिलता है।

ऐसे ही मेरे पड़ौस में एक छदामी है। सावन आते ही जिसका मनमयूर मचलने लगता है। बादलों को देखकर नहीं, बल्कि झुंड के झुंड जाते पैदलयात्रियों को देखकर। इस सीजन के आते ही छदामी हर साल किसी न किसी पैदल यात्रा में शामिल होने का जुगाड़ लगाने लगता है। वह तेल देखता है तेल की धार देखता है। उसके यार दोस्त इस बार किधर जाने की योजना बनाते है, उधर के अलावा छदामी किधर भी नहीं जाता।

आवारा बादलों की तरह घर से उसका मन उचटने लगता है। बन-ठनकर छदामी द्वार पर खड़ा हैं। हाथ में बेग, गले में माला, माथे पर तिलक, कंधे पर दुशाला। अब उसकी पत्नी को कौन समझाए जो रास्ता रोककर खड़ी है, कहती है—' ' हे भरतार, घर पर तो कभी ईश्वर को याद किया नही। सदकार्यों के लिए दान दिया नहीं। अब मत औरों पर भार बनो। फसल के बीच मत खरपतवार बनो।

ऐसे में छदामी को क्रोध आना स्वाभाविक था। वह बोला- अजीब

पहेली हो तुम ! न तो खुद चलती हो और न ही मुझे जाने देती हो।

क्या तुम नहीं चाहती कि हम धर्म-पुण्य कमाएं, पैदल चलकर बॉडी को फिट बनाएँ। पैदल यात्राओं के मजे तुम क्या जानो रामप्यारी? रामप्यारी अच्छी तरह जानती है। छदामी की नस-नस को पहचानती है। पैदल यात्रा तो एक बहाना है। मकसद तो घूमना - फिरना और मौज-मस्ती मनाना है। मजा आता है जब हुजूम का हुजूम हाथियों के दल की तरह एक साथ रोड़ पर चलता है। बेचारा हाई वे तक का ट्रैफिक तो इनके सामने हाथ मलता है।

स्वच्छता अभियान की असली परीक्षा ऐसे लोग ही लेते हैं। सारा रोड़ प्लास्टिक के पाउच, झूठे गिलास, बोतलों, प्लेटों, मूंगफली और केलों के छिलकों से पट जाता है। प्रदूषण के दूषण से ये धरती को धन्य कर देते हैं। गुटका, जर्दा तम्बाकू के रेपर से भर देते हैं। निर्बाध आपसी वार्तालाप का यह स्वर्णिम अवसर होता है। जितनी बातें साल भर में नहीं हो पाती उससे कई गुना बातें भीड़ के सखा-सखियों से जी भर कर हो लेती है। समाज की चौकसी से दूर नए रिश्ते बुनते हैं, पुराने मजबूत होते हैं। जो मजबूत हैं वे प्रगाढ़ होते हैं।

पैदल यात्राओं से ' 'गोरस बेचन हरिमिलन एक पंथ बहुकाज'' टाइप अनेक कारज सधते हैं। अजी हरिमिलन तो बाद की बात है। यह तो माध्यम है। भीड़ में भटकने के तो और भी कई मजे है।लोग जगह-जगह भंडारे सजाकर धर्मप्रेमी भक्तों का इंतजार करते है। चाय-पानी के लिए जगह-जगह मनुहार करते है। उनकी आड़ में ये छदामी जैसे छद्म भक्त भी मनुहार के हार को गले में डाल लेते हें। यानि इनकी भी हल्दी लगे न फिटकरी और रंग जोरदार आता है। कभी-कभी ये भररपूर आवाज में बजते डी. जे. की धुन पर पर, बीच सड़क पर डांस की खुन्नस निकाल डालते है। दोनो ओर का ट्रेफिक जाम करते है। इनको जाने के बाद ही रोड का जाम खुलता है। दोनो ओर के बस्ती वालों के कानों को सुकून मिलता है।

सो इस बार रामप्यारी ने दो टूक शब्दों में फरमान सुनाया - यहाँ घर पर ही कुछ काम करो। मत समय बरबाद करों। और कुछ नहीं तो कुछ पौधे रोपकर अपने नाम करो।' '

बेचारा छदामी इस बार मन मसोस कर रह गया। लोग जयकारे लगा रहे हैं, छदामी की हूक को जगा रहे हैं।

नागपंचमी विशेष

डॉ. तेज प्रकाश पूर्णानंद व्यास

(सर्प वैज्ञानिक)

नागपंचमी : सर्पदंश पर तत्काल चिकित्सा और जरूरी सावधानियां

भारतीय कोबरा का विष मुख्य रूप से हमारे तंत्रिका तंत्र (न्यूरोटॉक्सिक) पर सीधा प्रहार करता है, जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएँ बाधित होने लगती हैं। इसके भयावह लक्षण निम्नलिखित हैं- (अ) पलकों का गिरना- आँखों की पलकें भारी होकर अनैच्छिक रूप से गिरने लगती हैं, जिससे दृष्टि बाधित होती है।(ब) बोलने या निगलने में कठिनाई- विष के प्रभाव से जीभ और गले की मांसपेशियाँ प्रभावित होती हैं, जिससे आवाज लड़खड़ाने लगती है और भोजन या तरल पदार्थ निगलने में असहनीय परेशानी होती है। (स) मांसपेशियों में गंभीर कमजोरी- शरीर के विभिन्न हिस्सों में मांसपेशियों की शक्ति क्षीण होने लगती है, जो धीरे-धीरे बढ़ती हुई लकवे में बदल सकती है। (द) श्वसन संबंधी आपातकाल- यह विष श्वसन मांसपेशियों को पंगु बना देता है, जिससे सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है, जो तत्काल जीवन के लिए खतरा बन जाता है।

नागपंचमी के पावन पर्व पर, जब हम नाग देवता का सम्मान करते हैं, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उनके साथ जुड़े जीवन-रक्षक ज्ञान को भी समझें और जन सामान्य में साझा करें।

सर्पदंश: समय की बचत ही जीवन है

भारत में पाए जाने वाले लगभग 300 सर्प प्रजातियों में से, मानव जीवन के लिए घातक विषैले सर्प मुख्य रूप से 'बिग फोर' के नाम से जाने जाते हैं। इन चार सर्पों के दंश पर अविलंब प्रतिविष (एंटीवेनम) चिकित्सा ही जीवन रक्षक है।

भारत के 'बिग फोर' विषैले सर्प हैं: भारतीय कोबरा (नाग), कॉमन करैत, रसेल वाइपर तथा सॉ-स्केल्ड वाइपर। इनमें से किसी भी सर्प के दंश पर, पीड़ित को तत्काल अस्पताल ले जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्पदंश के उपरांत झाड़-फूंक, भोपा, गंडा-तावीज या किसी भी अप्रमाणित पारंपरिक उपचार के चक्कर में समय गंवाना मूर्खता है, जिससे बहुमूल्य जीवन का नुकसान हो सकता है।

सर्पदंश के लक्षण: प्रत्येक सर्प का विष अपने विशिष्ट गुणों के कारण शरीर पर भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभाव डालता है, जिससे लक्षणों में भी विविधता आती है।

1. भारतीय कोबरा (नाग) दंश के लक्षण (न्यूरोटॉक्सिक विष का भयावह प्रभाव)

भारतीय कोबरा का विष मुख्य रूप से हमारे तंत्रिका तंत्र (न्यूरोटॉक्सिक) पर सीधा प्रहार करता है, जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएँ बाधित होने लगती हैं। इसके भयावह लक्षण निम्नलिखित हैं: (अ)पलकों का गिरना: आँखों की पलकें भारी होकर अनैच्छिक रूप से गिरने लगती हैं, जिससे दृष्टि बाधित होती है। (ब) बोलने या निगलने में कठिनाई: विष के प्रभाव से जीभ और गले की मांसपेशियाँ प्रभावित होती हैं, जिससे आवाज लड़खड़ाने लगती है और भोजन या तरल पदार्थ निगलने में असहनीय परेशानी होती है। (स) मांसपेशियों में गंभीर कमजोरी: शरीर के विभिन्न हिस्सों में मांसपेशियों की शक्ति क्षीण होने लगती है, जो धीरे-धीरे बढ़ती हुई लकवे में बदल सकती है। (द) श्वसन संबंधी आपातकाल: यह विष श्वसन मांसपेशियों को पंगु बना देता है, जिससे सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है, जो तत्काल जीवन के लिए खतरा बन जाता है। (ई) मानसिक भटकाव और सुस्ती: रोगी भ्रमित, सुस्त या अचेत अवस्था में जा सकता है, जिससे प्रतिक्रिया करने की क्षमता कम हो

जाती है।

2. कॉमन करैत दंश के लक्षण- कॉमन करैत का विष भी अत्यंत शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके दंश की विशेषता यह है कि यह अक्सर रात में होता है और प्रारंभिक दर्द या सूजन न होने के कारण इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है, जिससे बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है: (अ) मांसपेशियों में गंभीर दर्द और ऐंठन: विशेषकर पेट और पीठ की मांसपेशियों में असहनीय दर्द और अकड़न महसूस होती है। (ब) पलकों का गिरना (Ptosis) और धुंधली दृष्टि (स) बोलने और निगलने में कठिनाई: बोलने में अस्पष्टता और निगलने में गंभीर समस्याएँ। (द) श्वसन पक्षाघात (ई)

चेतना का स्तर घटना (फ) अक्सर बिना दर्द के दंश।

3. रसेल वाइपर दंश के लक्षण

रसेल वाइपर का विष मुख्य रूप से रक्त (हीमोटॉक्सिक) और ऊतकों (साइटोटॉक्सिक) को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्सों में रक्तस्राव और ऊतक क्षति होती है। (अ) दंश स्थल पर असहनीय दर्द, सूजन और लालिमा (ब) व्यापक रक्तस्राव (स) रक्त का थक्का जमने में गंभीर समस्या (द) ऊतक क्षति और नेक्रोसिस (ई) मतली और उल्टी (फ) निम्न रक्तचाप (प) किडनी फेलियर।

4. सॉ-स्केल्ड वाइपर दंश के लक्षण (हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक विष का प्रभाव): सॉ-स्केल्ड वाइपर का विष भी रसेल वाइपर के समान ही हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक प्रभाव डालता है, हालांकि आमतौर पर इसके लक्षण रसेल वाइपर जितने गंभीर नहीं होते, फिर भी यह घातक हो सकता है (अ) दंश स्थल पर तेज दर्द और सूजन (ब) स्थानीय रक्तस्राव (स) रक्त का थक्का जमने में समस्या (द) मतली, उल्टी और पेट दर्द (ई) ऊतक क्षति (फ) बुखार और सामान्य अस्वस्थता: रोगी को बुखार और शरीर में सामान्य कमजोरी महसूस हो सकती है।

सामान्य चेतावनी: किसी भी सर्पदंश के बाद, चाहे प्रारंभिक लक्षण कितने भी हल्के या अनुपस्थित क्यों न हों, तत्काल बिना किसी देरी के प्रशिक्षित चिकित्सा सहायता लेना अनिवार्य है। तथाकथित 'ड्राई बाइट्स' (जहां सर्प ने विष नहीं डाला हो) के मामले में भी, किसी भी अप्रत्याशित जटिलता से बचने और रोगी को मानसिक रूप से आश्वस्त करने के लिए पूर्ण चिकित्सा जांच और निगरानी अत्यंत आवश्यक है। जीवन बचाने के लिए समय ही सबसे बड़ा कारक है।

तत्काल चिकित्सा: विषैले सर्प के दंश पर उपचार में देरी से बचने की संभावना काफी कम हो सकती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है अथवा गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। जब सांप का विष शरीर में फैलता है (सिस्टमिक एनवेनोमेशन), तो उसका प्राथमिक उपचार जिला शासकीय चिकित्सालय में पॉलीवैलेंट ASVS प्रतिविधि का उपयोग ही किया जाता है। यह एंटीवेनम भारत के 'बिग फोर' सर्प प्रजातियों के विष के खिलाफ प्रभावी है। ASVS में ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो सांप के विष में मौजूद विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करते हैं। सबसे प्रभावी होने के लिए, इसे काटने के तुरंत बाद, आदर्श रूप से पहले 30 मिनट के भीतर या इससे भी पूर्व समय में दिया जाना चाहिए। आमतौर पर, 8-10 शीशियाँ (प्रत्येक 10 मिली) पॉलीवैलेंट ASVS की शुरू में दी जाती हैं। इसे आमतौर पर एक घंटे में नसों में धीमे-धीमे या प्रति मिनट 2 मिलीलीटर की दर से इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। बाद की खुराक की आवश्यकता रोगी की नैदानिक प्रतिक्रिया और लक्षणों या असामान्य प्रयोगशाला परिणामों की निरंतरता से निर्धारित होती है। ASVS के अलावा, सहायक देखभाल भी महत्वपूर्ण है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में वर्तमान में उपलब्ध पॉलीवैलेंट ASVS मुख्य रूप से 'बिग फोर' के खिलाफ प्रभावी है। भारत में पाई जाने वाली अन्य विषैली सांप प्रजातियों, जैसे कि हंप-नोज्ड पिट वाइपर, के विष के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता सीमित या नगण्य हो सकती है।

नागपंचमी पर सांपों के प्रति हमारी श्रद्धा हमें उनकी सुरक्षा और हमारे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होने की याद दिलाती है। यदि दुर्भाग्यवश कोई सांप का शिकार हो जाए, तो तत्काल अस्पताल पहुंचना ही जीवन बचाने का एकमात्र मार्ग है। सर्पदंश की स्थिति में, सही प्राथमिक उपचार जीवन बचा सकता है, जबकि गलत कदम स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं।

विष निकालने के लिए घाव पर चीरा न लगाएं या मुंह से चूसने का प्रयास न करें। काटे गए स्थान पर टाइट पट्टी (टूर्निकेट) न बांधें।

बर्फ या अत्यधिक ठंडा नहीं लगाएं। फूंक, भोपा, गंडा-तावीज में समय व्यर्थ न गंवाएं। किसी भी प्रकार की जड़ी-बूटी या रसायन नहीं लगाएं ।

घाव पर कोई भी जड़ी-बूटी, तेल, या रसायन न लगाएं।

शराब या उत्तेजक पदार्थ देना

पीड़ित को शराब, चाय, कॉफी या कोई अन्य उत्तेजक पदार्थ न दें।

नागपंचमी पर, आइए हम प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा के साथ-साथ, जीवन बचाने के इस महत्वपूर्ण ज्ञान को भी फैलाएं। आपके जीवन में सुख-समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे।

धरती के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं नाग

नाग पंचमी पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

(लेखक 35 वर्षों से साहित्य एवं पत्रकारिता में निरन्तर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार तथा कई पुस्तकों के लेखक हैं)

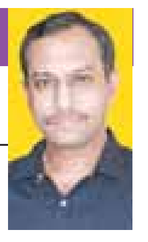

नाग पंचमी : कृषि मित्र नाग और उनकी दिव्यता का उत्सव

श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रतिवर्ष देशभर में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जो इस वर्ष 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में चैत्र तथा भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन भी 'नाग पंचमी' मनाई जाती है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, इसीलिए मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देवता की पूजा पूरे विधि-विधान से करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि के अलावा आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सर्पदंश के भय से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नाग पंचमी इस बार हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाई जाएगी। नाग पंचमी के दिन कुछ स्थानों पर 'कुश' नामक घास से नाग की आकृति बनाकर दूध, घी, दही इत्यादि से इनकी पूजा की जाती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर नागों के चित्र या मूर्ति को लकड़ी के एक पाट पर स्थापित कर मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल चढ़ाकर पूजन किया जाता है और पूजन के पश्चात् कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से नागराज वासुकि प्रसन्न होते हैं और पूजा करने वाले परिवार पर नाग देवता की कृपा होती है।

कुछ धर्म ग्रंथों में नागों को पूर्वजों की आत्मा के रूप में भी माना गया है। हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नागों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है और नाग पंचमी के दिन नाग पूजन करने का तो काफी ज्यादा महत्व माना गया है। भारत में कई स्थानों पर नाग देवता के कई प्राचीन मंदिर हैं और नागालैंड, नागपुर, अनंतनाग, शेषनाग, नागवनी, नागारखंड, भागसूनाग इत्यादि देश में कई स्थानों का तो नाम ही नागों के नाम पर ही रखा गया है। नागालैंड को तो नागवंशियों का मुख्य स्थान माना गया है और कुछ ग्रंथों में कश्मीर को भी नागभूमि कहा गया है। भारत में दक्षिण भारत के पर्वतीय इलाकों के अलावा उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम इत्यादि में नाग पूजा प्रमुखता से होती है।

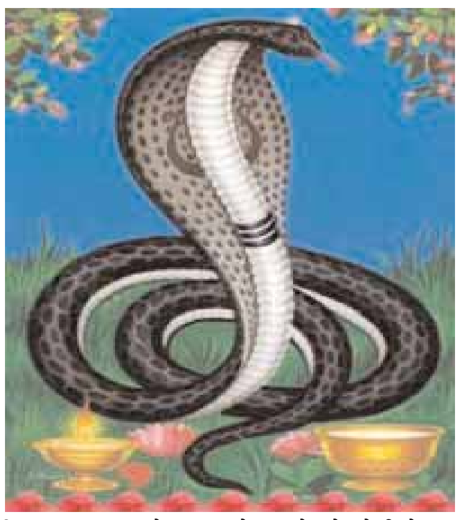

जिस प्रकार हमारे कुल देवताओं में देवी-देवता शामिल होते हैं, ठीक उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में नागों को भी 'स्थान देवता' माना जाता है। कई जगहों पर तो नागों को कुल देवता, ग्राम देवता और क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कुल 33 कोटि देवी-देवता हैं, जिनमें नाग भी शामिल हैं।

नागों की उत्पत्ति और उनके पाताललोक वासी होने को लेकर महाभारतकालीन एक कथा प्रचलित है। वराहपुराण के अनुसार, महर्षि कश्यप की तेरह पत्नियां थी, जिनमें से एक थी राजा दक्ष की पुत्री कद्रू, जिसने महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रू को वरदाने मांगने के लिए कहा। कद्रू ने उनसे एक हजार तेजस्वी नाग पुत्रों का वरदान मांगा। महर्षि कश्यप के वरदानस्वरूप कद्रू से ही नाग वंश की उत्पत्ति हुई लेकिन जब इन नागों ने धरती पर लोगों को डसना शुरू किया तो नागों से रक्षा के लिए सभी ने ब्रह्माजी से प्रार्थना की। तब ब्रह्माजी ने सभी नागों को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरीके से तुम लोगों पर अत्याचार कर रहे हो, अगले जन्म में तुम सभी का नाश हो जाएगा। यह श्राप सुनकर नाग भयभीत हो गए और उन्होंने कातर स्वर में ब्रह्माजी से प्रार्थना की कि जिस प्रकार मनुष्यों के रहने के लिए उन्हें पृथ्वी दी गई है, उसी प्रकार उन्हें भी इस ब्रह्माण्ड में कोई अलग स्थान दिया जाए, जिससे इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तब ब्रह्माजी ने उन्हें रहने के लिए पाताल देते हुए कहा कि अब से तुम सभी भूमि के अंदर पाताललोक में ही रहोगे। उसके बाद सभी नाग पाताललोक में निवास करने लगे। माना जाता है कि ब्रह्शाजी ने मनुष्यों की नागों से रक्षा के लिए जिस दिन उनके पाताल में रहने की व्यवस्था की, उस दिन सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तभी से इसी तिथि पर नागों की पूजा के लिए 'नाग पंचमी' त्योहार मनाया जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाग भगवान शिव के गले का हार तो हैं ही, भगवान विष्णु भी समुद्र में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और यह भी मान्यता है कि हमारी धरती इन्हीं शेषनाग के फन पर टिकी है। त्रेता युग में शेषनाग ने भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में धरती पर जन्म लिया था और द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम भी शेषनाग के अवतार माने गए हैं। वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नागों को कृषक मित्र जीव माना गया है। दरअसल ये खेतों में फसलों के लिए खतरनाक जीवों, चूहों इत्यादि का भक्षण कर फसलों के लिए मित्र साबित होते हैं लेकिन वर्तमान समय में नागों या सांपों की खाल, जहर इत्यादि चीजों से बड़े व्यापारिक लाभ के लिए बड़ी संख्या में इन्हें मारा और बेचा जाता है। इसी कारण वन्य और जीव-जंतु विभाग तथा सरकारों द्वारा नागों को संरक्षित करने के लिए सांपों को पकड़ने और उन्हें दूध पिलाने पर रोक लगाई जाती है।

सैयारा से संवेदना लेकिन रिश्तों से रुखापन

फिल्म के बहाने

सपना सी.पी. साहू 'स्वप्निल'

(लेखक और टिप्पणीकार)

नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा ने ऐसा क्या जादू किया कि सिनेमाघर आंसुओं के समंदर में डूब गए? रुमाल और टिशू पेपर का स्टॉक खत्म होने की कगार पर था। कोई बेहोश हो रहा था, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के गले लगकर सिसकियां ले रहा था। फिल्म खत्म होने पर कुछ को तो कुर्सी से उठाने के लिए चार लोगों का सहारा चाहिए था। लेकिन रुकिए जरा! यही युवा पीढ़ी है ना, जो अपने माता-पिता से सीधे मुंह बात करने में कतराती है? जिन्हें भाई-बहनों के जन्मदिन याद रखने के लिए रिमाइंडर लगाना पड़ता है? माता-पिता से फोन पर थोड़ी देर बात हो जाए, तो लगता है धरती का सबसे बड़ा अपराध हो गया। दादा-दादी, नाना-नानी के हालचाल पूछना तो दूर, उनके नाम तक इनके लिए धुंधले पड़ चुके हैं। इनके लिए रिश्ते वाई-फाई कनेक्शन जैसे हैं—सिग्नल अच्छा तो ठीक, वरना डिस्कनेक्ट! असल जिंदगी में इनकी संवेदनशीलता का मीटर शून्य से नीचे चल रहा है, लेकिन सैयारा में जैसे ही नायक-नायिका बिछड़ते हैं, इनके अंदर करुणा का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि सिनेमाघर डूबने लगता है।

हमारे देश की अजब-गजब युवा पीढ़ी का हाल देखकर आश्चर्य होता है। सिनेमाघरों में फिल्मी प्रेम कहानियों पर आंसुओं का सैलाब बहाते हैं, लेकिन असल जिंदगी के रिश्तों के लिए उनके दिल पत्थर से हो चुके हैं। गजब का दौर चल रहा है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सैयारा देखने का मौका मिला। सिनेमाघरों में युवा इस कदर बिलख-बिलखकर रो रहे थे, मानो सदियों का दर्द एक साथ उमड़ पड़ा हो। नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा ने ऐसा क्या जादू किया कि सिनेमाघर आंसुओं के समंदर में डूब गए? रुमाल और टिशू पेपर का स्टॉक खत्म होने की कगार पर था। कोई बेहोश हो रहा था, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के गले लगकर सिसकियां ले रहा था। फिल्म खत्म होने पर कुछ को तो कुर्सी से उठाने के लिए चार लोगों का सहारा चाहिए था। लेकिन रुकिए जरा! यही युवा पीढ़ी है ना, जो अपने माता-पिता से सीधे मुंह बात करने में कतराती है? जिन्हें भाई-बहनों के जन्मदिन याद रखने के लिए रिमाइंडर लगाना पड़ता है? माता-पिता से फोन पर थोड़ी देर बात हो जाए, तो लगता है धरती का सबसे बड़ा अपराध हो गया। दादा-दादी, नाना-नानी के हालचाल पूछना तो दूर, उनके नाम तक इनके लिए धुंधले पड़ चुके हैं। इनके लिए

रिश्ते वाई-फाई कनेक्शन जैसे हैं—सिग्नल अच्छा तो ठीक, वरना डिस्कनेक्ट! असल जिंदगी में इनकी संवेदनशीलता का मीटर शून्य से नीचे चल रहा है, लेकिन सैयारा में जैसे ही नायक-नायिका बिछड़ते हैं, इनके अंदर करुणा का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि सिनेमाघर डूबने लगता है।

हैरानी तब होती है, जब आई लव यू मॉम कहने में हिचकने वाले ये युवा फिल्म में आई मिस यू पर गला फाड़कर रोते हैं। क्या सैयारा का प्रेम इतना महान है कि ये अपने परिवार के सच्चे प्यार को भूल गए? अरे, यह प्रेम तो राधा-कृष्ण, शिव-गौरा के अमर प्रेम के सामने कहीं ठहरता ही नहीं! राधा-कृष्ण का प्रेम आत्मिक और दैवीय था, शिव-गौरा का प्रेम त्याग और समर्पण का प्रतीक है। और तो और, सैयारा का यह फिल्मी प्रेम तो लैला-मजनू, शीरी-फरहाद, या रोमियो-जूलियट के बराबर भी नहीं। ये ऐतिहासिक प्रेमकथाएं बलिदान, सच्चाई और गहरी भावनाओं की मिसाल थीं, जबकि सैयारा का प्रेम बस परदे की चमक, स्क्रिप्ट का जादू और मार्केटिंग का कमाल है। फिर भी, युवा इस काल्पनिक प्रेम में डूबकर आंसू बहाते हैं, जबकि असल जिंदगी के सुख-दुख उनके लिए बेमानी हैं।

आज के युवा अपनी सारी भावनाएं सोशल मीडिया पोस्ट्स और फिल्मों के लिए बचा रखते हैं। अपनों के सामने भावनाएं दिखाना उनके कूल और इमोशनलेस स्टेटस के खिलाफ है। शायद सैयारा ने इनके सोए हुए भावनात्मक तारों को झंकृत कर दिया, लेकिन यह संवेदनशीलता सिर्फ परदे तक सीमित क्यों? असल जिंदगी में ये क्यों नहीं अपने परिवार, दोस्तों या समाज के प्रति वैसी ही शिद्दत दिखाते? माता-पिता की छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखना, बुजुर्गों की चिंता करना, या भाई-बहनों के साथ वक्त बिताना—ये सब इनके लिए समय की बर्बादी क्यों लगता है?

कभी-कभी लगता है, ये आंसू शायद प्रैक्टिस हैं। ताकि जब असल में कोई भावनात्मक क्षण आए, जो आजकल के बच्चों के जीवन में कम ही आते हैं, तो इन्हें पता हो कि कैसे रोना है, कैसे भावनाओं का प्रदर्शन करना है। लेकिन यह प्रदर्शन सिनेमाघरों तक ही सीमित रहता है। असल जिंदगी में ये इमोशनल फूल कहलाने से डरते हैं। सैयारा ने निश्चित रूप से इनके दिलों को छुआ, लेकिन काश! यही संवेदनशीलता वे अपने वास्तविक रिश्तों में भी दिखाएं। खैर, सैयारा और इसके नए कलाकारों का डेब्यू शानदार रहा। फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि युवाओं के दिलों में गहरी छाप छोड़ी, पर ऐसी छाप रिश्तों, अपनेपन की उनके मन पर छुटे। वे परिवार और देश के लिए इतने संवेदनशील बने, अब बस उस दिन का इंतजार है। जब ये युवा असल रिश्तों को भी इतनी ही शिद्दत से महसूस करेंगे, देखना भारत में रिश्तों से खोता प्रेम फिर पनपेगा। जब ब्रेकअप और तलाक के झंझावात कम होंगे, और कोई रिश्ता नीले ड्रम या हनीमून की भेंट नहीं चढ़ेगा। जब ये युवा समझेंगे कि सच्चा प्यार सिनेमाई परदे पर नहीं, बल्कि उनके घर, परिवार और समाज मे बिखरा पड़ा है।

दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की डूबने से मौत

सेल्फी लेते समय हुआ हादसा, एसडीईआरएफ गोताखोरों ने पत्थरों के बीच से निकाला

बैतूल। बैतूल के खेड़ी के पास कन्हैया कोल झरने में रविवार को डूबे 16 साल के किशोर का शव सोमवार को बरामद कर लिया गया। एसडीईआरएफ की टीम ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से सुबह से

रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटे की तलाश के बाद पीयूष परिहार का शव झरने के पानी के गिरने वाली जगह पर एक चट्टान के नीचे फंसा हुआ मिला। पीयूष रविवार को अपने दोस्तों के साथ झरने पर घूमने गया था। वो सेल्फी लेने के दौरान गहरे पानी की ओर बढ़ गया। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो झरने में डूब गया। घटना के बाद से ही ग्रामीणों और पुलिस की मदद से तलाशी अभियान जारी था। तेज बहाव और पानी की गहराई के कारण रेस्क्यू में काफी कठिनाइयां आईं। सोमवार सुबह एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों के साथ मिलकर तलाशी अभियान तेज किया गया। दोपहर के समय शव पत्थरों के बीच फंसा हुआ मिला। खेड़ी चौकी प्रभारी राकेश सरेआम ने बताया कि किशोर के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है।

आउटसोर्स बिजली कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत

बैतूल। चिचोली-नसीराबाद-बीघवा मार्ग पर एक सडक़ हादसे में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो गई। उसकी पहचान वीरपुर निवासी सुरेंद्र यादव पिता सखाराम यादव के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार, सुरेंद्र यादव रविवार रात लगभग 10.30 बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने घर लौट रहा था। वह रातभर घर नहीं पहुंचा। सोमवार सुबह करीब 9 बजे नसीराबाद के पास सडक़ किनारे उसका शव और क्षतिग्रस्त बाइक मिली। स्थानीय लोगों ने तत्काल 100 डायल और थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करवाया। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। दोपहर में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एसडीओपी मयंक तिवारी ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह एक सडक़ दुर्घटना लगती है। बाइक फिसलने के निशान और उसके सीने पर आई चोटों के आधार पर पुलिस इसे हादसा मान रही है। हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

रजोनिवृत्त महिलाओं में अवसाद एक अनदेखा लेकिन गंभीर स्वास्थ्य संकट

भोपाल। एम्स भोपाल अपने कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में समावेशी और प्रमाण-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। संस्थान विशेष रूप से समाज के उन वर्गों की जरूरतों पर केंद्रित है जो अकसर अनदेखे रह जाते हैं। इसी क्रम में एम्स भोपाल ने रजोनिवृत्त अवसाद (पोस्टमेनोपॉज़ल डिप्रेशन) जैसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण, परंतु प्रायः उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे को रेखांकित किया है, जो न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि विश्वभर में लगभग 28 प्रतिशत रजोनिवृत्त महिलाएं अवसाद का शिकार होती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में यह स्थिति और भी गंभीर है। रजोनिवृत्त अवसाद के लक्षण अक्सर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के होते हैं, जिससे इन्हें सामान्य उम्र बढ़ने या रजोनिवृत्ति के लक्षण समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लगातार उदासी, चिड़चिड़ापन, निराशा, जीवन के प्रति रुचि में कमी, आत्मसम्मान की कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, थकावट, नींद और भूख में बदलाव, यौन इच्छा में गिरावट, सिरदर्द, शरीर में दर्द, सामाजिक अलगाव, आत्मग्लानि और गंभीर मामलों में आत्महत्या के विचार–ये सभी संकेत रजोनिवृत्त अवसाद की ओर इशारा करते हैं। रजोनिवृत्त अवसाद का उपचार रोगी की मानसिक अवस्था, अन्य चिकित्सकीय स्थितियों और उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। फार्माकोथेरेपी के तहत एसएसआरआई और एसएनआरआई जैसी एंटीडिप्रेसेंट दवाएं मध्यम से गंभीर अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति का उपचार मानी जाती हैं। हल्के अवसाद के मामलों में, खासकर जब अन्य रजोनिवृत्त लक्षण मौजूद हों, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर विचार किया जा सकता है। कई बार एंटीडिप्रेसेंट और हार्मोन थेरेपी का संयोजन भी प्रभावी सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हस्तक्षेप भी अवसाद के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ,विशेषकर उन महिलाओं के लिए अत्यंत प्रभावी है जो जीवन की सामाजिक या पारिवारिक चुनौतियों से जूझ रही हैं। इसके अलावा, सहायक परामर्श, समूह चिकित्सा, माइंडफुलनेस, योग और विश्रांति तकनीकें भी मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकती हैं।

इस गंभीर विषय पर प्रकाश डालते हुए प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, रजोनिवृत्त अवसाद केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्म-सम्मान, कार्यक्षमता और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली बहु-आयामी चुनौती है। एम्स भोपाल में हमारा प्रयास है कि हम इस मुद्दे पर व्यापक जागरूकता फैलाएं, प्रारंभिक जांच को बढ़ावा दें और रजोनिवृत्त महिलाओं को समग्र उपचार व सहयोग प्रदान करें।

कलेक्टर की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित

बैतूल। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आत्मा परियोजना के तहत किसानों के राज्य के अंदर और बाहर भ्रमण, फसल प्रदर्शन, तकनीकी वितरण, फॉर्म स्कूल इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्देशित किया कि आत्मा परियोजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से गवर्निंग बोर्ड ने सदस्यों को अवगत कराने और निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किए जाएं। बैठक में उप संचालक कृषि आनंद कुमार बड़ोनिया ने नैशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग के बारे में जानकारी अभियान के तहत जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित देने के लिए 6250 कृषकों का चयन किया गया है। जिनके द्वारा अपनी कृषि भूमि में एक एकड़ पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। जिसके लिए उन्हें हर साल चार हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। श्री बड़ोनिया ने बताया कि चयनित किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक क्लस्टर पर 2 कृषि सखी या सीआरपी होंगे। जिनके द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस महत्वपूर्ण अभियान के संबंध किसानों को जानकारी देने के लिए व्यापक जनजागृति अभियान चलाए।

जिले में 660 राशन दुकानों का होता है संचालन, 22 दुकानें सरेंडर

तीन समितियों ने राशन दुकान चलाने में जाहिर की असमर्थता

बैतूल। जिले में राशन दुकान चलाने से समितियों का मोह भंग होते जा रहा है। हाल ही में जिले की 3 समितियों ने राशन दुकानों के संचालन में असमर्थता जाहिर की है। बताया जा रहा है कि इन समितियों के अंतर्गत 22 राशन दुकानें संचालित होती थी। ऐसे में जिन दुकानों के संचालन के लिए समितियों ने असमर्थता जताई है, वहां दुकानों के संचालन के लिए जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को अलग से व्यवस्था करना पड़ रही है। बता दे कि जिले में 660 राशन दुकानों का संचालन हो रहा है। जिसमें राशन कार्डधारियों की संख्या 3.50 लाख से अधिक है। जबकि पात्र सदस्यों की संख्या 12.50 लाख के लगभग है। इन सभी पात्र सदस्यों को सरकार की तरफ से गेहूं, चावल का वितरण किया जाता है और हाल ही में सरकार की ओर से राशन उपभोक्ताओं को तीन माह का राशन एक साथ वितरित भी किया गया। लेकिन अब कुछ राशन दुकानदारों का कहना है कि सरकारी नीतियां उनके लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। कई समितियों को अपनी जेब से भी पैसे खर्च करने पड़ रहे है। जिससे वित्तीय बोझ बढ़ता है। यहीं कारण है कि समितियों ने दुकानों के संचालन के प्रति असमर्थता जाहिर की है।

कम कमीशन और डिजिटल व्यवस्था भी कारण– माना जा रहा है कि राशन दुकान संचालन पहले फायदे का सौदा हुआ करता था। राशन वितरण में मोटा कमीशन मिलने के साथ ही दुकान संचालक ऊपरी तौर पर भी कमा लेते थे, लेकिन सरकार ने जब से राशन

वितरण पीओएस मशीनों से ऑनलाइन शुरू किया हैं, तब से समितियों और दुकान संचालकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। सरकार से मिलने वाला कमीशन भी कम हो गया हैं। ऐसे में दुकान संचालकों को पाइ-पाइ अनाज का हिसाब भी देना पड़ रहा है। संचालकों के लिए दुकान चलाना अब सिरदर्द साबित होने लगा है। जिसके चलते दुकानों को संचालन करना समितियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।

भिन्न-भिन्न कारण बताकर कर रहे सरेंडर– एक समय था जब राशन दुकान लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, लेकिन अब राशन दुकान संचालक दुकान चलाने से हाथ खड़े कर रहे हैं। इसके पीछे दुकानदार व्यक्तिगत कारण बताते हुए दुकान संचालन में असमर्थता जाहिर की है। बताया गया कि आमला, शाहपुर और घोड़ाडोंगरी ब्लॉक की दुकानें सरेंडर की गई है। हालांकि चर्चा है कि कमीशन में कमी और डिजिटल व्यवस्था के चलते लाइसेंस सरेंडर किए जा रहे हैं। राशन दुकानदारों का कहना है कि उन्हें दुकान चलाने में कई समस्याएं आ रही हैं। मसलन कर्मचारी नहीं हैं। राशन की बिक्री से होने वाली कमाई बहुत कम है, जिससे दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है। दुकानदारों को अपनी जेब से भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ता है।

इन राशन दुकानों ने किया सरेंडर– जिले के आमला, शाहपुर और घोड़ाडोंगरी ब्लॉक की समितियों ने दुकानें के संचालन में असमर्थता जाहिर की है। इन समितियों के अंतर्गत धपाड़ा, भौंरा, कछार, झापड़ी, सालीमेट, मोतीढ़ाना, सिलपटी, पहावाड़ी, देशावाड़ी, सीवन पाट, लोनिया, खैरवानी, कुही, छुरी, सलैया, चि.आमढाना, कोलगांव, रमली, नांदपुर, बोडखी, गोठिया, जमदेही खुर्द की राशन दुकानें शामिल है। हालांकि 22 दुकानों के सरेंडर होने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन दुकानों के संचालन के लिए टेंडर निकाले गए है। हालांकि विभाग द्वारा इन दुकानों में अलग से व्यवस्था कर खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा हैं। राशन दुकान संचालन के लिए अब स्व सहायता समूहों को जिम्मेदारी सौंपने पर विचार किया जा रहा है।

इनका कनहा है –

जिले की 3 समितियों ने 22 दुकानों को सरेंडर किया है। इन दुकानों के संचालन के लिए टेंडर निकाले गए है। आवेदन आने के बाद जांच की जायेगी और अग्रिम कार्यवाही करेगे।

– कृष्ण कुमार टेकाम,
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी बैतूल

त्रिमूर्ति महादेव मंदिर पर महिलाओं द्वारा सवा लाख पार्थिव शिवलिंग बनाने का संकल्प पूर्ण

धार। त्रिमूर्ति नगर स्थित त्रिमूर्ति महादेव मंदिर पर एक भव्य आयोजन हुआ। सवा लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए गए और महा रुद्राभिषेक के साथ उनका पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में 140 विवाहित महिलाओं ने भाग लिया, जिन्होंने अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक किया।

महिलाओं द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाए जाने का संकल्प लिया गया था आज पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूर्ण हुए। सवा लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए गए, जिनका महा रुद्राभिषेक के साथ पूजन किया गया।

140 विवाहित जोड़ों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक किया। अभिषेक एवं पूजन का कार्यक्रम मंदिर के पंडित श्यामसुंदर दुबे के द्वारा करवाया गया।

पूजन के बाद सभी पार्थिव शिवलिंग देवी सागर तालाब पर में समाहित किए गए। उसके पश्चात महिला मंडल द्वारा आयोजन में शामिल सभी जोड़ों के लिए भोजन का आयोजन किया गया था।

श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती हैख।

त्रिमूर्ति महादेव मंदिर प्रमुख समाजसेवी अशोक मनोहर जोशी ने बताया कि त्रिमूर्ति महादेव मंदिर में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जोशी की स्मृति में जोशी परिवार द्वारा मंदिर की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी तथा उसके पश्चात विगत 4 वर्ष से हर श्रावण मास में सवा लाख पार्थिव शिवलिंग बनाने का संकल्प महिलाओं के द्वारा लिया जाता है इस क्रम में यह पार्थिव शिवलिंग तैयार किए गए । त्रिमूर्ति महादेव मंदिर धार शहर के मध्य त्रिमूर्ति नगर में स्थित है और त्रिमूर्ति नगर में श्री हरि और हर दोनों के ही मंदिर हैं इसलिए इस मंदिर की महत्ता और बढ़ जाती हैं और त्रिमूर्ति महादेव मंदिर में कई चमत्कार लोगों को देखने को मिले हैं ।

श्रावण माह की पावन बेला में इस अनूठे अवसर का लाभ लेने दूर- दूर से आ रहे श्रद्धालु..

धार। श्रावण माह की पावन बेला में ग्राम सिरसोदा में चल रहे महारूद्र अभिषेक में देश की 30 पावन नदियों के जल से विश्वंभर महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है। भारतवर्ष के इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है जब देवाधिदेव महादेव का देश के प्रमुख तीर्थों, पावन धामों से पावन नदियों का जल लाकर सिरसोदा की धरा पर महारूद्र अभिषेक में जलाभिषेक किया जा रहा है। यह संपूर्ण महारूद्र अभिषेक आचार्य पंडित विजय अग्निहोत्री कोद वालों के सानिध्य व आचार्यत्व में सहयोगी पंडित विकास चौबे के सहयोग से संपन्न हो रहा है। श्रावण माह की पावन बेला में इस अद्वितीय - अद्भुत अनूठे अवसर का लाभ लेने श्रद्धालु दूर- दूर से आ रहे है।

आचार्य पंडित विजय अग्निहोत्री ने बताया कि यह क्षेत्र के लिए दुर्लभ और अनूठा अवसर है जब भारतवर्ष की 30 पावन नदियों के पावन जल से महारूद्र अभिषेक किया जा रहा है। यमुनोत्री धाम से यमुना नदी का जल , गंगोत्री धाम से गंगाजल, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी का जल, बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा का जल और यही से मानागांव से सरस्वती नदी का जल लाया गया है। इसी तरह से अयोध्या से सरयू नदी का जल, कर्नाटक अंजनीपर्वत से तुंगभद्रा नदी का जल और द्वारिका नगरी (धाम) से गोमती नदी का जल लाया गया है। वही सोमनाथ से त्रिवेणी जल, श्री शैलम मलिकार्जुन से कृष्णा का जल, महेश्वर से मां नर्मदा का जल, घाटा बिल्लौद से चंबल का जल, पंजाब से सतलुज और व्यास का जल , त्रयंबकेश्वर से गोदावरी का जल, माही नदी और क्षिप्रा नदी सहित अन्य पावन नदियों से महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है।

ग्राम सिरसोदा में चल रहे महारूद्र अभिषेक में देश की 30 पावन नदियों से हो रहा विश्वंभर महादेव का जलाभिषेक

नित्य महादेव का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जा रहा है । अभिषेक पूरे दिन ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। संध्याकाल में आरती के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगणों द्वारा इन पावन नदियों का चरणामृत ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य मान रहे है।

बाढ़ में गर्भवती को बैलगाड़ी से पार करवाई नदी, बेटे को दिया जन्म

बैतूल। चिचोली ब्लॉक के बोड़ रैयत गांव में रविवार को एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। गांव के पास बहने वाली भाजी नदी बाढ़ से लबालब थी, लेकिन वहां पुल नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर महिला को बैलगाड़ी में बैठाया और नदी पार कराई। पानी के तेज

बहाव में बैलगाड़ी के आगे-पीछे ग्रामीण चल रहे थे, ताकि महिला को कोई नुकसान न हो। सुनीता को नदी पार करने के बाद चिरापाटला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां नर्स पूनम उईके की निगरानी में उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। सुनीता की सास रामवती उईके ने बताया कि नदी का बहाव इतना तेज था कि वह खुद बहते-बहते बचीं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने नदी पर पुल बनाने के प्रस्ताव को फिर से भेजने की बात कही है।

मध्य प्रदेश में नकली शराब का कहर

जीतू पटवारी ने सरकार की शराब नीति पर उठाए गंभीर सवाल, न्यायिक जांच की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों (2016-2025) में नकली और जहरीली शराब पीने से 1330 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, जिसने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और लापरवाह शराब नीति की पोल खोल दी है। इन मौतों पर गहरी चिंता जताते हुए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की 'शराब उदारीकरण नीति' ने शराब माफिया को बेलगाम कर दिया है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को भुगतना पड़ रहा है।

श्री पटवारी ने 2024-25 में रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों से सामने आ रही नकली शराब से मौतों की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा्यह साफ बताता है कि प्रदेश में शराब माफिया बेलगाम हो चुके हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि परिवारों के उजड़ने की दर्दनाक

कहानियां हैं।

शराब की बढ़ती खपत और 'उदारीकरण नीति' पर सवाल– श्री पटवारी ने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कहा मध्य प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में शराब पीने वालों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे आपकी सरकार की 'शराब उदारीकरण नीति' है, जिसने शराब को हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचा दिया है।

एनएफएचएस-5 रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया

*10.2 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू

*और 1 प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करती हैं

यह आंकड़े एक बड़ी चेतावनी हैं कि शराब अब सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रही, बल्कि महिलाओं और युवाओं तक भी इसकी पहुंच हो चुकी है। यह हमारे समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।

धार्मिक स्थलों की अनदेखी, महिलाओं में असुरक्षा और सामाजिक विघटन– श्री पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाया कि शराबबंदी वाले 19 शहरों और धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा है, जहां अब खुलेआम महंगी शराब बेची जा रही है। आपकी सरकार की नीतियां शराब के कारण बढ़ती घरेलू हिंसा, अपराध, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक विघटन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।

'एकीकृत स्वास्थ्य परिसर' की अवधारणा पर करें कार्य : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को एक साथ जोड़ते हुए 'एकीकृत स्वास्थ्य परिसर' की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फैकल्टी को अनुसंधान एवं नवाचार के अवसर, और मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ एक ही स्थान पर मिल सकें। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हों और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पुराने छात्रावास भवनों के जीर्णोद्धार, मल्टी लेवल पार्किंग, जीएमसी परिसर की एप्रोच रोड के सुधार, मेडिकल कॉलेज के रिडेवलपमेंट प्लान एवं चिकित्सकों, स्टाफ तथा फैकल्टी के लिए आवासीय क्वार्टर्स और अन्य सहायक सुविधाओं के विकास योजना के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने सामान्य सभा की 18 वी बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की वृहद समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में गाँधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की सामान्य सभा की 19वीं बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों, आय-व्यय, बजट तथा संस्थान के शैक्षणिक और भौतिक विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक में गाँधी मेडिकल कॉलेज के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इनमें नव प्रस्तावित मिल्क बैंक की स्थापना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का निर्माण, प्रोफेसर्स की पदोन्नति प्रक्रिया का समयबद्ध निराकरण, संस्थान में चल रहे शोध कार्यों को सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराने की नीति, विद्यार्थियों के लिए आधुनिक छात्रावास सुविधाओं का विस्तार जैसे बिंदु शामिल रहे। छात्र-छात्राओं के लिए 200 सीटों वाला छात्रा पीजी हॉस्टल तथा 400 सीटों वाला छात्र पीजी हॉस्टल की प्रगति की समीक्षा की और शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने हमीदिया अस्पताल भोपाल के हृदय रोग विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्हें अवगत कराया गया कि कार्डियोलॉजी विभाग की सेवाएँ वर्तमान में हमीदिया अस्पताल के ब्लॉक-1 की तीसरी एवं ग्यारहवीं मंजिल पर संचालित हैं। साथ ही, पुराने भवन में ट्रॉमा ब्लॉक के समीप स्थित कैथ लैब की वर्तमान कार्यप्रणाली से भी उन्हें अवगत कराया गया। उन्होंने विभाग के कामकाज, नॉन-इनवेसिव लैब की स्थिति तथा डीएम छात्रों के लिए चल रहे उच्चस्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सराहना की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ब्लॉक-1 की तीसरी मंज़िल पर नवीन कैथ लैब की स्थापना से हृदय रोग से पीड़ित गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों को और अधिक सुविधा मिलेगी। उन्होंने विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव गुप्ता एवं उनकी टीम को चिकित्सा शिक्षा, सेवा और शोध कार्यों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी। उन्हें विभिन्न इंटरवेंशन प्रक्रियाओं एवं रोगियों की संख्या की जानकारी भी दी गई।

बैठक में महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक श्री भगवानदास सबनानी, एमपीपीएचएससीएल के प्रबंध संचालक एवं कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष श्री मयंक अग्रवाल, जीएमसी की अधिष्ठाता डॉ. कविता सिंह, चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉ. अरुणा कुमार, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, फैकल्टी सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञ और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सभी के लिए नि :शुल्क उपलब्ध होगी शव फ्रीजर सेवा, श्री राम जन्म उत्सव समिति बस स्टैंड की पहल

बैतूल /मुलताई। किसी भी परिवार में मृत्यु होने पर परिजनों के आने तक शव को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती होता है। यह समस्या शव फ्रीजर ने बहुत हद तक कम कर दी है, किंतु इसकी उपलब्धता जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम है। जिसे देखते हुए श्री राम जन्मोत्सव समिति बस स्टैंड के सदस्यों ने आपकी सहयोग से 70 हजार रुपए की लागत से डेड बॉडी फ्रीजर बॉक्स(शव फ्रीजर) निशुल्क सार्वजनिक उपयोग के लिए खरीदा है। जन्मोत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय मोहित पाल की स्मृति में लाए गए इस शव फ्रीजर को बस स्टैंड डॉ. कृष्णा धोटे की क्लीनिक पर रखा गया है, जहां से आवश्यकता होने पर कोई भी व्यक्ति उपयोग के लिए इसे ली जा सकता है। यहां उल्लेखनीय है कि पवित्र नगरी में जनसंख्या के आधार पर शव फ्रीजर की कमी बड़ी समस्या है। नगर वासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव फ्रीजर उपलब्ध हो लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। जिसे महसूस करते हुए श्री राम जन्म उत्सव समिति के सदस्यों ने आपसी सहयोग से यह शव फ्रीजर उपलब्ध कराया है। इस समिति के सदस्यों का उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसमें सभी युवा शामिल है जो समय-समय पर धार्मिक कार्यो का साथ ही जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जानकारी के अभाव में खराब हो रहे हैं शव फ्रीजर– पवित्र नगरी में शव को सुरक्षित रखने के लिए नगर के अनेक सामाजिक संगठन अपने-अपने सामाजिक स्तर पर शव फ्रीजर उपलब्ध कराते हैं लोगों का कहना है कि जो लोग इसे शव सुरक्षा के लिए ले जाते हैं वह लोग इसका ध्यान नहीं रख पाते। उपयोग की सही जानकारी न होने कारण अब यह फ्रीजर खराब होने लगे हैं। मुलताई नगर में गुरुद्वारा साहिब, साहू समाज, कुनबी समाज और मुस्लिम समाज के पास यह शव फ्रीजर उपलब्ध है। सभी का कहना है कि उपयोग के लिए ले जाने वाले लोग इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते जिससे यह खराब होने लगे हैं। सबसे पहले तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद इसे कम से कम 45 मिनट बाद प्रारंभ करें ताकि फ्रीजर की गैस स्थिर हो सके। यह फ्रीजर ऑटोमेटिक होता है इसका टेंपरेचर कम ज्यादा करने के लिए इसके साथ छेड़ छडी ना करें।

विश्व बाघ दिवस पर विशेष

आरबी त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

बाघ उवाच; हमारे आपके कुनबे के लिये जंगलों को बचायें

विश्व बाघ दिवस के कुछ दिन पहले बाघों को लेकर अच्छी खबरें सामने आई। राजस्थान में जयपुर के नज़दीक नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रानी नामक बाघिन ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया। इनमें एक सफेद शावक भी शामिल है। चार माह बाद इन्हें डिस्प्ले एरिया में लाया जायेगा जिससे कि सैलानी इनका दीदार कर सकें। इधर मध्यप्रदेश के सिवनी में हाल ही में बाघिन के साथ सड़क पर चार शावक विचरण करते देखे गये। इसी तरह की खबरें प्रदेश के बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना टाइगर रिजर्व सहित देश के अन्य राज्यों में स्थित टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और अभयारण्यों से सुर्खियां बनी है जिनमें बाघिनों के साथ शावक अठखेलियाँ करते नज़र आ रहे हैं। निश्चित ही ऐसी खबरें उत्साहजनक कही जाना चाहिये कि आगामी टाइगर सेंसश जो 2026 में होना है उसमें बाघों की फिर से बहार आयेगी।

एक और अच्छी ख़बर यह है कि सरकार द्वारा रातापानी अभयारण्य को प्रदेश का 8 वां टाइगर रिजर्व पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम से तथा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी को 9 वें माधव टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इसी तरह सागर जिले में डॉ अम्बेडकर अभयारण्य सागर के रूप में गठित किया गया है। उधर यूनेस्को ने प्रदेश के 3 प्रमुख टाइगर रिजर्व पेंच, कान्हा तथा बांधवगढ़ को बायोस्फियर रिजर्व का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे इन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान, रिसर्च तथा पर्यटन के क्षेत्र में नये मार्ग मिल सकेंगे।

हालांकि विभिन्न कारणों के चलते कई जगहों से बाघों की मौत की खबरें भी सामने आती रही है। साथ ही आबादी इलाकों के नज़दीक बाघों की मौजूदगी और उनकी दहाड़ भी सुनाई दे जाती है। हमेशा की तरह इसकी मुख्य वज़ह जंगलों के क्षेत्रों का घटना, आग, पानी के प्राकृतिक स्त्रोतों की कमी तथा बाघों के इलाकों में इंसानों की घुसपैठ , रिसॉर्ट, फार्म हाउस, भवनों सहित अन्य निर्माण की बढ़ती प्रवृत्ति है। नतीजतन राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर हाईवे और आबादी के आसपास के इलाकों में बाघों का विचरण करना पाया जाता है। इसीलिए बाघ जंगली जानवर के साथ अपवाद स्वरूप इंसानों पर भी हमला कर देते हैं ।

दूसरी तरफ वन विभाग की तमाम चौकसी और सतर्कता के बावजूद शिकारियों से बाघों, तेंदुओं के अंग अवशेष बरामद होते हैं। बीते जून माह में ही माधोपुर श्योपुर कराहल रोड पर 3 शिकारियों को गिरफ्तार कर इनके पास से बरामद अवशेष को जांच के लिये बेंगलुरू भेजा गया है।

स्टेट टाइगर फोर्स द्वारा बाघ की तस्करी में 9 साल से फरार अंतरराष्ट्रीय तस्कर ताशी शेरपा को नेपाल- भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास दार्जिलिंग में गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। इस मामले में न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा शेरपा को 5 साल के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में शिकारी से लेकर बिचौलिये तथा तस्कर समेत 28 आरोपियों को सजा दी गई है। इसके लिये इंटरपोल फ्रांस द्वारा टाइगर फोर्स को उत्कृष्ट कार्य के लिये हाल ही में प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है।

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अर्थॉरिटी (एनटीसीए) की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में साल 2024 में 126 टाइगर की मौतें विभिन्न वजहों के चलते हुई। इनमें टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश में 46 और महाराष्ट्र में 23 बाघों की मौत शामिल है जो चिंताजनक है। हमारे देश में 2022 की गणना में 3682 बाघ पाये गये थे जो विश्व भर में पाये जाने वाले बाघों का 75 फीसदी है। हमारे लिये गौरव की बात है कि प्रदेश 785 बाघों के साथ देश में सिरमौर है। बाघों की अगली गणना (एस्टीमेशन) 2026 में होगी। यानी इंसानों की जनगणना और बाघों की गणना लगभग एक साथ होगी। इसे कहते हैं हम साथ- साथ हैं।

वनराज, जंगल के राजा टाइगर या शेर जंगलों कंदराओं में ही अच्छे लगते हैं। ये किसी तरह की नुमाइश के लिये नहीं बने हैं। लेकिन हमारे पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान से आई खबरों में खुलासा हुआ है कि वहां टाइगर/ शेर को पालतू बनाकर पिंजरों में कैद कर पाला जा रहा है। इस अमूल्य धरोहर की वहां खरीद - फरोख्त होती है। इस तरह इस मुल्क को चिड़ियाघर बना रखा है।

उधर चीन के एक रेस्त्रां में चाय पान के दौरान शेर के शावकों को गले लगाने, उन्हें गोद में लेकर फोटो खिंचवाने की पेशकश की जा रही है। हालांकि पशु अधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना भी की है। उधर पर्यटन प्रधान देश थाईलैंड में तो यह सब बहुत पहले से हो रहा है। वहां वनराज को गले में पट्टा या जंजीर डालकर घुमाया भी जाता है। वहां भी शावकों को गोद में बैठाकर पर्यटक फोटो खिंचवाते हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान यह सब देखा भी है। सो, मध्यप्रदेश को यूं ही अजब-गजब प्रदेश कहा जाता है जबकि अजब-गजब तो ये देश कहलाने चाहिये।

मध्यप्रदेश में बाघों के साथ तेंदुओं की भी बहुतायत है। साल 22 की गणना अनुसार तेंदुओं की संख्या 3907 है। लेकिन विभिन्न कारणों से बीती छःमाही में 32 तेंदुओं की मौतें रिपोर्ट हुई। प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बड़े जोरशोर के साथ हवाई मार्ग से लाये गये चीतों की भी खबर लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नामीबिया से यहां लाई गई मादा चीता नाभा ने बीते दिनों इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शिकार की कोशिश में उसे चोटें आई थी। अब कूनो में 26 चीते बताये जाते हैं जिनमें 9 वयस्क और 17 भारत में जन्मे शावक शामिल हैं। यहां भी मादा चीता ज्वाला अपने तीन शावकों के साथ नजर आई।

संक्षिप्त समाचार

जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर आयोजित

बैतूल (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय बैतूल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज हुरमाड़े ने बताया कि शिविर में 101 गर्भवती महिलाओं की चिकित्सकीय जांच हुई, इनमें 33 गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क के रूप में चिन्हित किया गया। इनकी नियमित निगरानी कर उचित प्रबंधन के साथ ही सुरक्षित प्रसव करवाया जाएगा, 76 गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की गई। शिविर में समस्त महिलाओं की खून की एवं जीडीएम की जांच की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ ईशा डेनियल द्वारा 40 गर्भवती महिलाओं की जांच एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आठनेर में स्त्री रोग चिकित्सक डॉ रूपल श्रीवास्तव द्वारा 107 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें 32 हाई रिस्क महिलाएं पाई गई। सीएमएचओ डॉ हुरमाड़े ने बताया कि शिविर का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य संस्था में आवश्यक जांचे, चिकित्सकीय परीक्षण, परामर्श और हाई रिस्क महिलाओं का उचित प्रबंधन कर संस्थागत सुरक्षित प्रसव करवाना है, जिससे मातृ एवम शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।

जीवन और मृत्यु के बीच झूलता नन्हा अभय, सामूहिक प्रयास से मिला जीवनदायी सहारा

बैतूल (निप्र)। जिले के भैंसदेही ब्लॉक में एक बार फिर सरकारी तंत्र और सामाजिक जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण सामने आया है। हाल ही में दस्तक अभियान के तहत आयोजित पोषण क्लिनिक में जब 1.1 वर्ष के अभय को देखा गया, तो स्वास्थ्य कर्मियों के होश उड़ गए। अभय का वजन मात्र 4 किलोग्राम था, जो उम्र के लिहाज से बेहद कम है और गंभीर कुपोषित है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक थी, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती थी। पोषण क्लिनिक में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम द्वारा जब अभय की स्थिति को पहचाना गया, तो उन्होंने तुरंत परिवार को एनआरसी में भर्ती करवाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि परिजनों ने कई प्रयासों के बावजूद सहयोग नहीं किया। सामाजिक मान्यताएं, जानकारी की कमी और अस्पतालों को लेकर लोगों के मन में व्याप्त डर इस असहयोग का मुख्य कारण बना। जब स्थानीय स्तर पर समझाइश से बात नहीं बनी, तो मामले को एसडीएम भैंसदेही तक पहुंचाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, और अंतरा फाउंडेशन की संयुक्त टीम ने मिलकर परिजनों से संपर्क साधा। एसडीएम के मार्गदर्शन और संवेदनशील संवाद के बाद अंततः परिजनों ने अभय को एनआरसी में भर्ती कराने पर सहमति दी। इसके बाद अभय को तत्काल पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी में भर्ती कर लिया गया है, जहां उसे जीवन रक्षक उपचार, चिकित्सकीय देखरेख और पोषण संबंधी विशेष देखभाल मिल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि समुचित देखभाल से अभय की स्थिति में सुधार होगा और वह जल्द ही सामान्य विकास की ओर लौटेगा।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का जीवन चरित्र समाज के लिए प्रेरणादायकः जनजातीय मंत्री श्री विजय शाह

बैतूल (निप्र)। मप्र के जनजातीय मंत्री श्री विजय शाह शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर बैतूल पहुंचे। इस दौरान स्थानीय सर्किट हाउस पर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जनजातीय मंत्री श्री शाह का पुष्प गुच्छ से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री श्री शाह को जनसंपर्क विभाग द्वारा मध्य प्रदेश संदेश वाचन की प्रति ससम्मान भेंट की गई। इस अवसर पर जनजातीय मंत्री श्री शाह ने अहिल्या बाई होल्कर को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन चरित्र पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। आधुनिक समाज में अपने क्रियाकलापों, न्याय व्यवस्था से अहिल्या माता ने समाज और देश को सशक्त मार्ग दिखाया है। उनका शासन काल सुराज, स्वराज, सुशासन, सुव्यवस्था, संपन्नता, विकास और निर्माण का पर्याय था।

खाद की कालाबाजारी और नकली खाद बेचने वालों के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें: केन्द्रीय मंत्री

रायसेन जिले को विकास और जनकल्याण के मामले में मॉडल बनाएं,जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। विदिशा के सांसद व केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य राज्यमंत्री तथा उदयपुरा विधायक श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, नर्मदापुरम सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा, सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, भोजपुर विधायक श्री सुरेन्द्र पटवा, स्थानीय जनप्रतिनिधी तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित है। बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया तथा जिला अधिकारियों द्वारा विभागवार संचालित योजनाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी गई। बैठक के प्रारंभ में केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में सभी को अपने पूरी क्षमता से काम करना होगा। शासन द्वारा नशामुक्त समाज बनाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। यह अभियान या प्रयास नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। जिले में जहां भी कार्यक्रम हों वहां नागरिकों को नशामुक्ति का संकल्प जरूर दिलाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि जिले में कही भी अवैध रूप से मदिरा का विक्रय ना हो, यदि कहीं बिकती है तो कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मदिरा ही नहीं ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थो पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए।

आमजन के कल्याण और विकास को केन्द्र में रखकर काम करें : केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए सरकार की योजनाओं और विकास कार्यो का लाभ आमजन तक पहुंचे। आमजन का कल्याण और विकास प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य यही है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों का लाभ सुगमता से समय से नागरिकों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य को लेकर सभी समन्वित प्रयास करें। रायसेन जिले को विकास और जनकल्याण के मामले में मॉडल बनाएं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करें। जो भी पात्र व्यक्ति योजना के हितलाभ से वंचित रह गया है तो उसे शीघ्र योजना का लाभ दिलाया जाए। इसी प्रकार विकास और निर्माण कार्यो पर नजर रखे, विकास के काम गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण हों जिससे कि आमजन को उनका शीघ्र लाभ मिले।

निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हों इसके लिए सघन मॉनीटरिंग की जाए : बैठक में केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत जिले में संचालित विकास कार्यो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मनरेगा आदि की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आवास प्लस के कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि योजना का क्रियान्वयन इस प्रकार हो कि हितग्राहियों को समय पर किश्त की राशि जारी हो। उन्हें अधिक समय तक इंतजार ना करना पड़े। सभी पात्र हितग्राहियों के नाम आवास सूची में शामिल हो। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को निर्माण सामग्री सस्ती दर पर सुगमता से मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जाएं। निर्माण कार्यो में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो तथा कार्य समय पर पूरे हो इसके लिए जिला स्तर पर सघन मॉनीटरिंग की जाए। वर्ष 2024-25 में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कुल 27981 आवास स्वीकृत किए गए जिनमें से 4825 पूर्ण हो गए हैं तथा 23156 प्रगतिरत हैं।

जिले में हैं 43613 लखपती दीदियां : केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यो की समीक्षा के दौरान कहा कि स्वसहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें, उनका सर्वागीण विकास हो ! इसके लिए जिले में विशेष कार्य किए जाएं। ग्रामीण महिलाओं को परम्परागत व्यवसायों की जगह नए व्यवसायों की ओर अग्रसर किया जाए। उन्होंने जिले में लखपति दीदियों की संख्यात्मक जानकारी लेते हुए कहा कि अधिक से अधिक महिलाएं, बहनें लखपति दीदी बनें इसके लिए कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के सभी विकासखण्डों में कुल 10293 स्व-सहायता समूह हैं जिनमें 113485 सदस्य हैं।

नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का जिलेभर में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन

बैतूल (निप्र)। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण और महिला सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवांकुर सखी योजना के अंतर्गत पांच दिवसीय हरियाली यात्रा का जिले के सभी विकास खंडों में व्यापक आयोजन किया जा रहा है। यात्रा का शुभारंभ हरियाली अमावस्या के शुभ अवसर पर किया गया, जिसमें जिले के ग्रामीण अंचलों में सैकड़ों नवांकुर सखियों ने भाग लिया। हर नवांकुर सखी को 11 बीज रोपित एवं अंकुरित पौधों की थैलियां वितरित की गईं उन्हें वे अपने घरों में पालेंगी और वर्षभर विभिन्न शुभ अवसरों पर पौधारोपण करेंगी। यह अभिनव पहल पूरे प्रदेश में 1 लाख 56 हजार 500 सखियों के माध्यम से 17 लाख 21 हजार 500 पौधों के रोपण का लक्ष्य लेकर चलाई जा रही है।

पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ग्राम में निकाली कलश यात्रा : विकासखण्ड आठनेर के ग्राम हिवरा में कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कलश यात्रा से हुआ। जनपद पंचायत आठनेर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री आस्था जैन ने महिलाओं को पर्यावरण व शासन की योजनाओं में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया। ÷एक पेड़ मां के नाम÷ अभियान के अंतर्गत 5 फलदार पौधों का स्कूल परिसर में रोपण किया गया। विकासखंड भैंसदेही के ग्राम देड़पानी नवांकुर संस्था देड़पानी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विकासखंड समन्वयक विकास कुमरे ने सखी योजना पर प्रकाश डाला। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सूरजलाल जावरकर, सरपंच रविकिशोर अखंडे, एनआरएलएम प्रतिनिधियों और ग्रामीण महिलाओं की विशेष उपस्थिति रही।

नवांकुर सखियों को बीज रोपित पौधे किए वितरित : घोड़ाडोंगरी में डॉ. मनोज पाटनकर, जनपद सदस्य प्रदीप विश्वास, पार्षद नेहा उइके सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों नवांकुर सखियों की सहभागिता रही। नवांकुर संस्था देवी सोशल वर्क एवं एजुकेशन सोसाइटी और प्रस्फुटन समिति के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ।

विकासखंड प्रभात पट्टन के ग्राम बिसनुर में विकासखंड समन्वयक राधा बरोदे द्वारा योजना की जानकारी दी गई। कलश यात्रा का नेतृत्व सरपंच प्रियंका ठाकरे और जनपद सदस्य जयश्री पाटणकर ने किया। तहसीलदार यशवंत सिंह गिनारे द्वारा बीज की पन्नियां वितरित की गईं। विकासखण्ड शाहपुर के ग्राम टांगनामाल में नवांकुर संस्था सुमन जन जागृति समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 100 नवांकुर सखियों को बीज रोपित पौधे वितरित किए गए।

कलेक्टर ने की नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा जलमग्नीय पुल-पुलिया पार नहीं करने की अपील

बाढ़ संभावित ग्रामों एवं स्थानों में नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक कदम उठाने के जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को दिए निर्देश

सीहोर (निप्र)। लगातार हो रही भारी वर्षा, बारना एवं तवा बांध के गेट खोलने तथा बरगी बांध से जल निकासी की मात्रा बढ़ाने से नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने सभी नागरिकों से अपील की है कि बाढ़ प्रभावित तथा जलभराव वाले संभावित निचले स्थानों में नहीं जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें।कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने जिला प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आगामी समय में बाढ़ प्रभावित एवं जलभराव वाले स्थानों तथा ग्रामों में सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने पुल, पुलियों, रपटों के ऊपर पानी होने पर आवागमन बंद करने तथा जोखिम पूर्ण स्थान पर जाने से नागरिकों को रोकने के निर्देश दिए हैं। पुल-पुलिया, रपटों, नदी-नाले पार नहीं करने की अपील कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि लगातार हो रही वर्षा के कारण जिन पुल, पुलिया, रपटों के ऊपर पर पानी बह रहा हो, उन्हें पार नहीं करें। उन्होंने नागरिकों से यह भी अपील की है कि बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर जाये तथा उन मार्गों से नहीं जाएं जिनपर नदी-नालों पर बने पुलों के ऊपर पानी होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है। आवश्यक होने पर आवागमन के लिए सुरक्षित मार्गों का उपयोग करें।

बेतवा नदी के किनारे बसे परिवारों का सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण

विदिशा (निप्र)। जिले में हो रही लगातार भारी वर्षा एवं बेतवा नदी के जल स्तर में वृद्धि को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नदी किनारे बसे परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है। नगर पालिका सीएमओ श्री दुर्गेश सिंह ने बताया कि नगर पालिका दल ने 20 परिवारों के कुल 73 लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया है। विस्थापित परिवारों को तुरंत राहत उपलब्ध कराते हुए भोजन एवं आवश्यक सामग्री वितरित की गई। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को तत्काल सूचना देकर सहयोग करें।

संकट की घड़ी में स्पॉन्सरशिप योजना बनी सहारा

स्पॉन्सरशिप योजना से धनवंतरी चौहान के बच्चों की उम्मीदों को मिली नई उड़ान

सीहोर (निप्र)। गरीबी और विपत्तियां जब जीवन के द्वार पर दस्तक देती हैं, तब सरकारी योजनाएं यदि संवेदनशीलता से लागू हों, तो वे किसी देवदूत से कम नहीं होतीं। ऐसी ही एक जनकल्याणकारी योजना है स्पॉन्सरशिप योजना। जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलाई जा रही है। स्पॉन्सरशिप योजना, सरकार की एक संवेदनशील और व्यावहारिक पहल है, जो बच्चों को उनके परिवार में ही सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती है। सीहोर निवासी श्रीमती धनवंतरी चौहान भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं जिनकी दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिला है। श्रीमती धनवंतरी कहती हैं कि उनके जीवन में अचानक अंधकार तब छा गया, जब कोरोना काल में उनके पति का निधन हो गया। घर चलाने वाले का साया उठ गया और दो छोटी बेटियों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई।

उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि बेटियों की पढ़ाई और भविष्य का क्या होगा। जब सभी रास्ते बंद से लगने लगे, तभी उन्हें अपने वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से इस योजना की जानकारी मिली। उन्होंने आवेदन किया और कुछ ही समय बाद उनकी दोनों बेटियों को दो-दो हजार रूपये प्रतिमाह मिलने लगे। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से श्रीमती धनवंतरी की दोनों बेटियों को की पढ़ाई को नई दिशा मिली। उनकी दोनों बेटियां नियमित रूप से स्कूल जाती हैं और मन लगाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हैं। श्रीमती धनवंतरी चौहान कहती हैं कि यह योजना सिर्फ सहायता राशि नहीं देती, यह टूटे हुए परिवारों को फिर से खड़े होने की ताकत भी देती है। इस योजना के लिए श्रीमती धनवंतरी चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है।

क्या है स्पॉन्सरशिप योजना : यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एक योजना है। यह योजना गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे उन बच्चों के लिए संचालित की जा रही है जिनके माता-पिता नही हैं अथवा माता-पिता में से किसी एक का निधन हो गया है तथा जिनके पास भरण-पोषण या शिक्षा का कोई स्थायी साधन नही है। इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक बच्चे को दो हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के लिए जिले की बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से आवेदन किया जाता है। इसके पश्चात घर की स्थिति की जांच की जाती है तथा पात्र पाए जाने पर योजना स्वीकृत होती है और राशि मिलना प्रारंभ होती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जा रही हैं निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य केंद्रों में की गई 335 गर्भवती महिलाओं की जांच

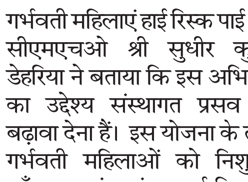

सीहोर (निप्र)। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिये प्रत्येक माह की 09 एवं 25 तारीख को जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर देखभाल एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निशुल्क लाभ प्रदान किया जा रहा है, ताकि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अभियान के तहत 25 जुलाई को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 335 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें 163 गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क पाई गईं। सीएमएचओ श्री सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क जाँच, दवाएं, एवं परामर्श दिया जा रहा है। अभियान के तहत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं विशेष देखभाल की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत प्रसव के समय जटिल अवस्था में उच्च चिकित्सा केन्द्रो में रेफर किया जाता है।

राइट क्लिक

क्या पिपलोदी हादसा भी 'हत्या' ही नहीं है...?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल बिल्डिंग की छत अचानक गिरने से उसके नीचे बैठकर ज्ञान का ककहरा सीख रहे 7 बच्चों की मौत जैसी ह्रदय विदारक घटना का पहला सबक तो यह है कि अब आप किसी भी स्कूल में पढ़ाई, शिक्षक व अन्य सुविधाओं के साथ यह खात्री भी करें कि स्कूल की बिल्डिंग भी मजबूत है या नहीं। शिक्षा की रोशनी का नन्हा सा दिया कहीं उसके नीचे दबकर बुझ तो नहीं जाएगा? क्योंकि पता नहीं आपके नौनिहाल जिस छत के नीचे भविष्य के सपनों की मासूम रेखाएं खींच रहे हों, वही न जाने कब दगा दे जाए। प्राकृतिक या अन्य कारणों से इतर यह ऐसा हादसा है, जिसके लिए पूरी तरह सरकार, व्यवस्थाक और समाज जिम्मेदार है। जान बूझकर की गई लापरवाही और संवेदनहीनता जिम्मेदार है। पिपलोदी की इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। क्योंकि इस देश में अभिभावक अभी तक अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल तक पहुंचाने, स्कूल के भीतर उनकी आबरू बचाने, पढ़ाई ठीक से होने और बच्चों का भविष्य संवरने की चिंता से ही जूझ रहे थे। अब इसमें स्कूल की वह इमारत भी शामिल हो गई है, जिसे सुरक्षित छत मानकर बच्चे तो क्या बड़े भी आंतरिक सुकून महसूस करते आ रहे हैं। दुर्योग से पिपलोदी की घटना के साल भर पहले अफ्रीकी देश नाइजीरिया के जोस शहर में भी ऐसा बड़ा हादसा हुआ था। जिसमें एक स्कूल बिल्डिंग अचानक ढहने से अंदर परीक्षा दे रहे 22 बच्चों को उत्तर पूरा लिखने के पहले ही असमय अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस हादसे में अपने किशोर बेटे और बेटी को गंवाने वाले पिता माइकल ओनोवो ने कहा था-' यह हादसा नहीं, हत्या है! बताया जाता है कि इस घटना में अपुष्ट जानकारी के अनुसार करीब 50 बच्चों की मौत की हुई थी, जो शायद किसी चलते स्कूल के बीच मासूम बच्चों के मरने सबसे बड़ा और डरावना आंकड़ा है। फर्क इतना है कि नाइजीरिया की वह बिल्डिंग एक निजी स्कूल की थी और मरने वाले बच्चे हादसे के वक्त परीक्षा दे रहे थे तो पिपलोदी के स्कूल की जर्जर इमारत सरकारी थी और वहां बच्चे रोजाना की तरह सबक याद कर रहे थे। दोनो में एक समानता है और वो है- स्कूल इमारत का घटिया निर्माण और रखरखाव में लापरवाही। नाइजीरिया के मामले में वहां के प्रशासन ने उसे 'अपरिहार्य घटना' बताया तो पिपलोदी मामले में स्कूल, जिला प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने में लगा है। आशय यही कि जो हुआ, वह 'ईश्वरेच्छा' थी। इसमें कोई क्या कर सकता है। यह नकारात्मक सोच इस बात का सबूत है कि सरकार और प्रशासन किस असंवेदनहीन तरीके से काम करते हैं। उन्हें इससे शायद ही मतलब हो कि नाइजीरिया के माइकल ओनोवो की तरह पिपलोदी में भी छोटूलाल ने अपने दोनो बच्चों को गंवा दिया है। उन बच्चों की मां के सारे सपने स्कूल भवन के मलबे में राख हो गए हैं।

इस बीच इस घटना से चिंतित केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने यहां सरकारी स्कूल भवनों का ऑडिट करने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने भी जर्जर स्कूल भवनों में फिलहाल बच्चो को न पढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहां के शिक्षा मंत्री ने मदन दिलावर ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली है, लेकिन इस्तीफे से इंकार किया है। लेकिन असल सवाल तो यह है कि सरकारी स्कूल भवन इतनी जल्दी जर्जर कैसे हो जाते हैं, क्यों समय रहते उनकी मरम्मत नहीं होती, क्यों हर दो-तीन साल में स्कूल भवनों का ऑडिट नहीं होता? क्या इसलिए कि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं? क्या इसलिए कि शिक्षा के सुदृढ़ मंदिर बनाने से ज्यादा हमारी रूचि उसकी निर्माण राशि हड़पने में है? और क्या शिक्षा हमारी आस्था का विषय नहीं है? अगर राम मंदिर का निर्माण हजार साल की आयु को ध्यान में रखकर हो सकता है तो शिक्षा मंदिर का निर्माण कम से कम सौ साल के लिए तो हो ही सकता है। पिपलोदी स्कूल के मामले में भी यही सामने आ रहा है कि गांव वालों और शिक्षकों ने भी भवन के जीर्णशीर्ण होने की शिकायत प्रशासन से की थी, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता लेना जरूरी नहीं समझा। शायद उन्हें सात मासूम बच्चों की लाशें उठने का इंतजार था।

यहां बात अकेले राजस्थान की नहीं हैं, जहां कुल 9 लाख 13 हजार 50 स्कूलों में से 2 हजार स्कूल के भवन जीर्णशीर्ण हालत में है, बल्कि मध्यप्रदेश सहित अधिकांश राज्यों की यही स्थिति है। मप्र में 211 स्कूलों के पास भवन ही नहीं है। 1275 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है तो 12 हजार से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। राज्य सरकार ने एक अधिकृत जवाब में माना कि मप्र में 5600 स्कूल भवनों की हालत जर्जर है। कई स्कूलों में बारिश में छत से पानी टपक रहा है तो स्कूल के प्लास्टर उखड़ना और दीवारें गिरना असाधारण बात नहीं है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही पिछले दिनों एक पीएमश्री स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्रा घायल हो गई थी। 67 हजार में फर्नीचर और 15 हजार विद्यालयों में बिजली तक नहीं है। 2,787 स्कूलों में बालिका शौचालय ही नहीं हैं , हैं तो किसी काम के नहीं है। यहां तक कि बालकों के लिए भी 3116 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता कमलनाथ ने हाल में आरोप लगाया था कि मप्र शिक्षको के 70 हजार पद खाली हैं और 15 हजार शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हैं। हालांकि मप्र सरकार ने अब स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 13 हजार स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। लेकिन यह भी नाकाफी है। स्कूल भवनों के रखरखाव के लिए कितना बजट है, यह स्पष्ट नहीं है।

यह स्थिति तकरीबन देश के सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश वर्तमान में कुल 10 लाख 22 हजार 386 सरकारी स्कूल हैं। यह भारत भर के कुल स्कूलों की संख्या का 68.7 फीसदी है। इसका अर्थ यही है कि देश में स्कूली शिक्षा में अभी भी सरकारी स्कूलों की अहम भूमिका है। इन स्कूलों में कुल स्कूली बच्चों के 54 प्रतिशत बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल कुल शिक्षकों का 51.4 रोजगार देते हैं। देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में यानी 16 लाख से ज्यादा से हैं। उसके बाद राजस्थान और मध्यप्रदेश का नंबर है। हालांकि देश में सबसे अच्छा छात्र शिक्षक अनुपात यूपी में है।

ऐसा नहीं है कि सरकारें शिक्षा के लिए बजट नहीं दे रही हैं या फिर बढ़ा नहीं रही हैं। हालांकि यह बजट नीति आयोग दवारा प्रस्तावित कुल जीडीपी के 6 फीसदी से अभी भी कम है, जबकि होना चाहिए। वर्ष 2024-25 के बजट में मोदी सरकार ने शिक्षा के लिए 1.20 लाख करोड़ रू. का प्रावधान किया था। न केवल केन्द्र बल्कि अधिकांश राज्यों में भी शिक्षा के लिए बजट बढ़ तो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है, वह बड़ा सवाल है। स्वीकृत बजट में से भी ज्यादातर खर्च उन चुनिंदा स्कूलों पर ही हो रहा है, जिसे सरकार 'वीआईपी' मानती है। दूरदराज के सरकारी स्कूल राम भरोसे हैं। जबकि शिक्षा और उसका अधिकार सबके लिए बराबर है और होना चाहिए। इसमें गांव और शहर का भेदभाव भी अस्वीकार्य है। पिपलोदी हादसे में भी हमेशा की तरह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। गिरी छत तुम्हारे शासन में बनी कि हमारे शासन में, यह मूर्खता पूर्ण बहस केवल जनता को धोखा देना है। जबकि शिक्षा और वो भी स्कूली शिक्षा राजीनीति का विषय होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि शिक्षा देश की नई पीढ़ी को सुशिक्षित और उसे योग्य इंसान बनाने का उपक्रम है। दरअसल स्कूली शिक्षा को दोयम दर्जे का मानकर उसे हिकारत की नजर देखना भी अपने आप में बड़ा सामाजिक और मानव विकास की दृष्टि से महापाप है। पिपलोदी का हादसा भी इस मायने में 'हत्या' ही है। इसे सिर्फ इसलिए अनदेखा नहीं किया जा सकता कि स्कूल की छत ढह जाने से वहां पढ़ रहे जो फूल असमय कुम्हला गए, उनमें आपका बच्चा नहीं था।

शव पहुंचाने अस्पताल से घर तक मिलेंगे नि:शुल्क वाहन

सीएम ने 148 शव वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कल से ही पूरे प्रदेश में मिलेगी सुविधा

भोपाल (नप्र)। मप्र में किसी मरीज या घायल की मौत हो जाने पर अस्पताल से मृतक के घर तक शव ले जाने के लिए परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क शव वाहन की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश भर के लिए 148 शव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल, स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र पटेल मौजूद थे।

सीएम बोले- साइकिल, बैलगाड़ी पर शव ले जाते समाचार देखे हैं- शव वाहनों को हरी

झंडी दिखाने के बाद सीएम ने मीडिया से चर्चा में कहा- मप्र सरकार द्वारा कई प्रकार की जनहितैषी और संवेदनशील योजनाएं लागू की है। वो योजनाएं कई राज्यों में पहली बार लागू हुई हैं। ऐसी एक अत्यंत संवेदनशील बड़ी योजना लागू हो रही है। हम समाज के साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसे एम्बुलेंस लेकर अस्पताल आती है और उसे इलाज मिलता है।

लेकिन, किसी कारण वश शरीर छूट गया ऐसे में वो गरीब आदमी है साधन विहीन है दूर कहीं जाने वाला है तो वो अपने परिजन की लाश को कई बार साइकिल पर, हाथ में, बैलगाड़ी में ले जाते हुए कई बार समाचार पत्रों में न्यूज चैनल पर दृश्य देखे हैं।

हमने ये घोषणा की थी कि योजना में इस प्रकार का साधन बनाएंगे कि कोई अपने स्वजन को मृत अवस्था में घर तक ले जाना चाहते हैं तो सरकार उसको शव वाहन की सुविधा देगी।

हर जिले में रहेंगे दो शव वाहन- सीएम ने कहा- बाकी देश के लिए हम आदर्श स्थिति में आ रहे हैं। पूरे देश में मप्र एकमात्र सरकार ये सुविधा दे रही है जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में 148 शव वाहन की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। जहां प्रत्येक जिले में दो शव वाहन सरकारी अस्पताल में किसी की मृत्यु होने पर वो शव को घर तक पहुंचाकर आएंगे। जहां मेडिकल कॉलेज हैं वहां दो-दो एक्स्ट्रा शव वाहन दे रहे हैं। कुल मिलाकर 4 शव वाहन अपने जिले के अंदर इस व्यवस्था के लिए रहेंगे।

कुल मिलाकर ये हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है और हमारी भावना है। हम सब सरकार की योजनाओं के माध्यम से उन समस्याओं का हल कर रहे हैं जो परस्पर एक दूसरे की पूरक हों।

फ्री मिलेगी सुविधा आज से होगी लागू

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह योजना चालू की है। हम शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। ये जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्ट्म के बाद शव पहुंचाने के लिए शव वाहन की निःशुल्क मिलेगी।

इसका पूरा खर्च मप्र सरकार उठाएगी। कल से ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। मप्र ने इससे पहले एयर एंबुलेंस की सुविधा भी दी है।

राहगीर योजना से जान बचाने वालों को देंगे 25 हजार

मप्र विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन ही रहा हंगामेदार

गिरगिट लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 28 जुलाई पहले दिन सोमवार को कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वे हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले गिरगिट लेकर पहुंचे। गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण नहीं देना चाहती। वह बार-बार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है।

वहीं, सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा- मुझे चिंता है कि कमलनाथ जी को सदन में आने से कौन रोक रहा है? मुझे लगता है कि यह कांग्रेस की गुटबाजी और फूट का परिणाम है।

दिवंगत नेताओं, पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद विस मंगलवार तक स्थगित - सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूर्व विधायक राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह, रघुनाथ चौधरी, शंकर लाल मुन्नाखेड़ी, सरदार सुखदेव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय कुमार रूपाणी, फिल्म अभिनेता मनोज कुमार, लोक कलाकार रामसहाय पांडे को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

3 सरकारी विधेयक, अनुपूरक बजट आएगा- 8 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र के लिए कुल 3377 में से 2076 सवाल ऑनलाइन आए हैं जबकि ऑफलाइन सवालों की संख्या 1301 है। 226 ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प की 23 और शून्यकाल की 65 सूचनाएं विधायकों की ओर से दी गई हैं। विधायकों ने नियम- 139 के तहत एक सूचना दी है। एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी सचिवालय को दी गई है। इस सत्र में तीन सरकारी विधेयक भी पेश किए जाएंगे।

महेश परमार बोले- जनप्रतिनिधियों को रोकना चाह रही सरकार- तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा- सरकार इतनी डरी हुई है कि जन प्रतिनिधि और मीडिया को विधानसभा कार्यवाही से दूर रखना चाहती है। लेकिन हम पुरजोर तरीके से अपनी बात रखेंगे ताकि प्रदर्शन पर रोक के फैसले को सरकार वापस ले। परमार ने उज्जैन में महाकाल दर्शन को लेकर अनियमितताओं को लेकर संबंधित अफसरों पर कार्रवाई की मांग भी की।

सदन में उठ सकता है प्रदर्शन पर रोक का मुद्दा

विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों को पत्र भेजकर विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन न करने को कहा गया है। विपक्षी विधायक इस मुद्दे को सदन में उठा सकते हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बीती 10 जुलाई को सभी विधायकों को एक परिपत्र भेजा था। इसमें सुरक्षा का हवाला देते हुए व्यवस्था में सहयोग करने की अपेक्षा की गई है। इसमें लिखा था कि विधानसभा परिसर और दर्शक दीर्घा में प्रवेश पत्र सीमित संख्या में जारी किए जाएंगे। विधायकों से अनुरोध है कि अपने एक निज सहायक और ड्राइवर का नाम, गाड़ी नंबर के साथ प्रवेश पत्र कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को कांग्रेस ने तीखे तेवर दिखाए। कांग्रेसी विधायक हाथों में तख्तियां और गिरगिट के खिलौने लेकर पहुंचे। गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण नहीं देना चाहती। वह बार-बार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है।

अंजना ने की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतेह

मैहर की बेटी ने माउंट एल्ब्रस पर सुबह 6 बजे लहराया तिरंगा

मैहर (नप्र)। मैहर जिले के छोटे से गांव बेंदुरा कला की बेटी अंजना सिंह ने देश का नाम रोशन किया है। अंजना ने यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस (5,642 मीटर/18,510 फीट) पर 27 जुलाई को सुबह 6 बजे सफलतापूर्वक चढ़ाई कर भारत का तिरंगा फहराया।

शिखर पर पहुंचकर अंजना ने राष्ट्रगान गाया। उन्होंने बर्फीली हवाओं और ऑक्सीजन की कमी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी अपना साहस दिखाया।

अंजना के पिता राजेश सिंह एक छोटे किसान हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद अंजना ने पर्वतारोहण में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और मार्गदर्शक एडवोकेट शिवेंद्र सिंह बघेल को दिया। अंजना ने कहा कि उस बर्फीले पहाड़ पर मैंने जो भी कदम रखा, वह मेरे माता-पिता के त्याग और मेरे गुरु के मार्गदर्शन से प्रेरित था। यह जीत मुझसे ज्यादा उनकी है।

18 जुलाई से शुरू हुई यात्रा- अंजना की यात्रा 18 जुलाई को मैहर से शुरू हुई। वह 21 जुलाई को दुबई पहुंचीं। फिर 22 जुलाई को रूस रवाना हुईं। 23 जुलाई को बेस कैंप पहुंचने के बाद 24-25 जुलाई को चढ़ाई शुरू की। 26 जुलाई को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें विश्राम करना पड़ा। 27 जुलाई को रात 2 बजे अंतिम चढ़ाई शुरू की और सुबह 6 बजे माउंट एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक पहुंचीं।

हरियाली तीज के उपलक्ष्य में त्रिपुर सुंदरी वूमेंस ग्रुप द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या मे महिला उपस्थित रहे कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताएं हुई तथा महिलाओं में बहुत उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सभी को प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरित किए गए। त्रिपुर सुंदरी वूमेन ग्रुप की सदस्यों ने मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया। त्रिपुर सुंदरी ग्रुप के सदस्य नीतू तिवारी, कृति शर्मा, राखी शर्मा, निहारिका दुबे, शामली शर्मा ,सुजाता, संगीता तिवारी, दीप्ति गोरखे सभी सदस्य मौजूद थे।

बिजली बिल के लिए भी पावर गेम

लगता है, सत्ता के गलियारों में हवा का रुख बदला है। जिन सीनियर आईएएस अफसर की तूती बोलती थी, आज उनकी बत्ती गुल होने की नौबत आ गई है! सूत्रों की मानें तो एक दौर में खास मंजिल के 'दमदार अधिकारी' रहे ये साहब,

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

अब ऐसे विभाग में विराजमान हैं जहाँ उन्हें अपने विभाग के दफ्तरो की बिजली के बिल भुगतान के लिए ऊर्जा विभाग से 'सख्त पत्र' मिल रहे हैं। यह कोई मामूली बिल नहीं, जनाब, करोड़ों में है! और मज़े की बात ये कि, जो अफ़सर साहब को बिल भरने की 'हिदायत' दे रहा है, वह भी अब उसी 'खास मंजिल की कुर्सी' पर कब्ज़ा जमा चुका है। लगता है, मंत्रालय में 'पावर गेम' सिर्फ सत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि बिजली के बिलों के लिए भी खेला जा रहा है। अब देखना ये है कि साहब की बत्ती गुल होती है, या 'पावर' वापस आती है!

जब मौसी ने IPS को धकेला

मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को एक प्रदर्शनी अवलोकन के दौरान बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। जब मुख्यमंत्री प्रदर्शनी का जायज़ा ले रहे थे, तो उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी थे। तभी हमारी सबकी प्यारी पूर्व विधायक शबनम मौसी वहां पहुंचीं। मौसी, मुख्यमंत्री से बतियाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ीं, तो एक सीनियर आईपीएस अफसर ने उन्हें रोकने की गुस्ताखी कर दी। फिर क्या था! मौसी ने अपने चिर-परिचित अंदाज़ में आईपीएस साहब की छाती पर दोनों हाथ मारे और उन्हें धकेल कर पीछे कर दिया। इसके बाद मौसी ने मुख्यमंत्री को भरपूर आशीर्वाद दिया। इस दिव्य क्षण के साक्षी बने विधानसभा अध्यक्ष और नगरीय प्रशासन मंत्री भी मौसी के आशीर्वाद से अछूते नहीं रहे। लगता है, मौसी ने यह साबित कर दिया कि कुछ आशीर्वाद प्रोटोकॉल से ऊपर होते हैं, और कुछ अधिकारी साइड में ही ठीक लगते हैं!

सांसद का 'वन मैन शो'

प्रदेश भाजपा में नव नियुक्त अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को प्रभावित करने की होड़ ज़ोरों पर है। नव नियुक्त अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इन दिनों दौरे पर हैं और पार्टी की नब्ज़ टटोल रहे हैं। हाल ही में जब अध्यक्ष महोदय महाकौशल के सबसे बड़े जिले में पहुंचे, तो वहां के सांसद महोदय ने वन मैन शो का ऐसा जलवा बिखेरा कि बाकियों की तो बोलती ही बंद हो गई! सांसद ने न केवल अध्यक्ष का ज़बरदस्त स्वागत किया, बल्कि एक भव्य रोड शो भी निकलवाया, जिसमें वह पूरी तरह से छाए रहे। बेचारे जिले के अन्य भाजपा विधायक, जो इस कार्यक्रम में तवज्जो की आस लगाए बैठे थे, उन्हें सिर्फ दर्शकों की भूमिका में ही संतोष करना पड़ा। अब सुनने में आ रहा है कि इस वन मैन शो को लेकर अन्य विधायकों में काफी नाराज़गी है। लगता है, राजनीति में केवल वन मैन शो ही चलता है, बाकी सब बैकग्राउंड में रह जाते हैं!

सरकार का बैकफुट

हरदा के लाठीचार्ज में लगता है सरकार ने किरकिरी से बचने के लिए बैकफुट पर आने की कला में महारत हासिल कर ली है। हरदा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज ने जो बवंडर उठाया और उस पर कांग्रेस व करणी सेना के राष्ट्रीय नेताओं की आवाजाही ने आग में घी डालने का काम किया। अब सूत्र बताते हैं कि सरकार को डर सता रहा था कि कहीं उनके अपने ही खासकर राजपूत विधायक, विधानसभा सत्र में पुलिस की बर्बरता को लेकर सरकार की किरकिरी न कर दें। भले ही सरकार अधिकारियों के प्रति नरम रुख अपनाए हुए थी, लेकिन भाजपा विधायकों के उग्र तेवरों व दबाव से बचने के लिए, सत्र शुरू होने से ठीक पहले हरदा के तीन पुलिस अधिकारियों को हटाकर सरकार ने अपनी किरकिरी होने से बचा ली। वाह रे, यह बैकफुट की रणनीति कितनी दूर तक चलती है, या फिर अगली किरकिरी के लिए नया ब्रेकफुट तैयार करना पड़ेगा!

जब PS ने अफसरों को फटकारा

वल्लभ भवन में इन दिनों अफसरों की क्लास लग रही है, और इस क्लास के टीचर हैं प्रमुख सचिव। निर्माण विभाग की बैठक में प्रमुख सचिव ने ENC सहित तमाम अफसरों को न केवल फटकार लगाई, बल्कि एक सेवानिवृत्त सलाहकार अफसर को तो हटाने तक के निर्देश दे दिए।

मामला था प्रदेश की सड़कों पर मौजूद दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट और उन्हें दुरुस्त करने पर होने वाले करोड़ों के खर्चे का। जब प्रमुख सचिव ने इस पर अधिकारियों से चर्चा की, तो हमारे WRD और ENC ऑफिस के अफसर बगले झांकने लगे। जैसे पूछ लिया हो कि आज डिनर में क्या है? वहीं, NHAI के अफसरान ने तुरंत पीएस को ब्रीफ कर अपनी नेकनीयती का सबूत दिया। लेकिन विभाग के अफसरों की खामोशी पीएस को रास नहीं आई। फिर क्या था! उन्होंने ENC, CE और EE तक के अफसरों को जमकर फटकारा। और हां, जो सेवानिवृत्त सलाहकार अफसर वहां अपनी सलाह देने आए थे, उन्हें तो तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के निर्देश दे दिए गए। लगता है, ब्लैक स्पॉट सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि कुछ विभागों में भी हैं।